सत्यमेव जयते

आर्थिक समीक्षा
2024-25

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली–110001
जनवरी, 2025

विषय सूची

	vii	*प्रस्तावना*
	xiii	*आभारोक्ति*
	xv	*संकेताक्षर*
	xxxiii	*तालिकाओं की सूची*
	xxxv	*चार्टों की सूची*
	xliii	*बॉक्स की सूची*
अध्याय सं.	**पृष्ठ सं.**	**अध्याय का नाम**
1		**अर्थव्यवस्था की स्थितिः पुनः तेज़ गति की ओर**
	2	परिचय
	2	वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
	11	वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है
	20	कई मोर्चों पर अर्थव्यवस्था, स्थिरता और समावेशिता से अभिलक्षित होती है
	32	दृष्टिकोण और भावी संभावनाएं
2		**मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकासः अन्योन्याश्रयी संबंध**
	36	परिचय
	36	मौद्रिक विकास
	38	वित्तीय मध्यस्थता
	74	भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जोखिम
	77	दृष्टिकोण
3		**बाह्य क्षेत्रः एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना**
	80	परिचय
	82	वैश्विक व्यापार गतिशीलता
	93	भारत के व्यापार प्रदर्शन में रुझान
	103	निर्यातकों के लिए व्यवसायिक पहल करने की सुगमता
	104	भुगतान संतुलनः चुनौतियों के बीच सुदृढ
	117	दृष्टिकोण
4		**कीमतें और मुद्रास्फीतिः उतार-चढ़ाव को समझना**
	120	परिचय
	120	वैश्विक मुद्रास्फीति
	122	घरेलू मुद्रास्फीति
	131	दृष्टिकोण और भविष्य की दिशा
5		**मध्यम अवधि का परिदृश्यः गैर-विनियमन से विकास को बढ़ावा**
	135	भारत का मध्यावधिक दृष्टिकोण
	137	भू-आर्थिक विखंडन - इस बार स्थिति अलग हो सकती है

141 स्पष्ट अंतर्निहित समस्या

143 जलवायु परिवर्तन, चीन और भू-राजनीति

149 भारत की विकास संभावनाओं के निहितार्थ

151 विकास के आंतरिक साधनों को पुनर्जीवित करना-गैर-विनियमन के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना

6 **निवेश और अवसंरचनाः अनवरत रहे**

165 परिचय

166 चुनाव पश्चात अवसंरचना के पूंजीगत व्यय में सुधार

167 भौतिक कनेक्टिविटी

176 विद्युत क्षेत्र

178 डिजिटल कनेक्टिविटी

180 ग्रामीण अवसंरचना

183 शहरी अवसंरचना

188 पर्यटन अवसंरचना

189 अंतरिक्ष अवसंरचना

190 निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

7 **उद्योगः समग्र व्यवसायी सुधार**

193 वैश्विक पृष्ठभूमि

195 हालिया घरेलू घटनाक्रम

196 मुख्य निविष्टि उद्योग

199 पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों का प्रदर्शन

204 उन्नत अनुसंधान एवं विकास की आकांक्षाओं के बीच बढ़ते नवाचार

209 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

212 औद्योगिक उत्पादन में राज्यवार पैटर्न में अधिक समानता लाने के लिए उपयुक्त नीतियों की संभावना

219 निष्कर्ष और दृष्टिकोण

8 **सेवाः दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियाँ**

221 परिचय

223 भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

225 वित्तपोषण के स्रोतः बैंक ऋण और एफडीआई

228 लॉजिस्टिक्स और फिजिकल कनेक्टिविटी-आधारित सेवाओं में प्रगति

232 अन्य सेवाएँ

234 व्यापार सेवाएँ

240 सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन का राज्यवार विश्लेषण

246 निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

9 **कृषि और खाद्य प्रबंधनः भविष्य का क्षेत्र**

247 परिचय

252 फसल उत्पादन: उत्पादकता वृद्धि, फसल विविधीकरण और इनपुट के उपयोग में दक्षता को प्रोत्साहन देना
253 बीज-गुणवत्ता और उर्वरकों का उपयोग: महत्वपूर्ण विभेदक
253 वर्षा और सिंचाई प्रणाली: दक्षता निर्माण और कवरेज का विस्तार
259 कृषि ऋण: एक महत्वपूर्ण इनपुट
262 कृषि यंत्रीकरण: अभिगम को सुगम बनाना
263 कृषि विस्तार: सक्षमकता
263 कृषि विपणन अवसंरचना में सुधार
265 कृषि में जलवायु का प्रभाव
266 संबद्ध क्षेत्र: समुत्थानशीलता सृजन की संभावना
268 सहकारी समितियाँ: बेहतर सेवा के लिए संस्था को मजबूत बनाना
269 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण
269 खाद्य प्रबंधन: खाद्य सुरक्षा को सक्षम बनाना
271 निष्कर्ष

10 जलवायु और पर्यावरण: अनुकूलन की अनिवार्यता
273 परिचय
276 अनुकूलन को सबसे आगे लाना
282 ऊर्जा संचरण-विकसित देशों के अनुभव से सीखना और विकल्पों पर विचार करना
289 भारत के ऊर्जा संचरण की दिशा में की गई प्रगति
295 सतत विकास के लिए जीवन शैली का अनुकूलन
299 वायु प्रदूषण
300 निष्कर्ष

11 सामाजिक क्षेत्र: पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन
303 परिचय
310 शिक्षा : नए रास्ते पर चलना
329 एक स्वस्थ राष्ट्र की ओर
351 ग्रामीण अर्थव्यवस्था
361 दृष्टिकोण

12 रोजगार और कौशल विकास: अस्तित्वगत प्राथमिकताएँ
363 परिचय
366 रोजगार की स्थिति
387 रोजगार सृजन: रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में कदम
398 कौशल विकास: बदलती दुनिया के लिए अप-स्किलिंग, री-स्किलिंग और न्यू-स्किलिंग
411 निष्कर्ष

13 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई) युग में श्रम व्यवस्था : संकट या उत्प्रेरक?

413 परिचय
416 क्रांतियाँ और हलचल
419 मजबूत संस्थाओं की आवश्यकता
421 दृष्टि से व्यवहार्यता की ओर: एआई के लिए प्रत्यक्ष चुनौतियाँ
426 एआई और भारत: क्या अवसर हैं?
429 श्रम बाजार का विकास
431 भारत के सेवा क्षेत्र का संवर्धन
436 निष्कर्ष

प्रस्तावना: गैर-विनियमन के माध्यम से घरेलू विकास और समुत्थानशीलता को बढ़ावा देना

गैर-विनियमन के माध्यम से व्यवसाय की लागत को कम करना अप्रत्याशित वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होगा

जब आप इस दस्तावेज और इस प्रस्तावना का अवलोकन कर रहे होंगे तो पिछले आर्थिक सर्वेक्षण को आए छह महीने से ज्यादा समय हो चुका होगा। पिछला सर्वेक्षण हुए अभी कम ही समय बीता है इसलिए इसे देखते हुए, सैद्धांतिक रूप से तो इस प्रस्तावना में लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। किंतु वास्तविकता में देखें तो बहुत कुछ है। दुनिया, जितना हम समझते हैं; संभवत: उससे कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रही है। इतिहास के लंबे दौर में, यह उम्मीद के मुताबिक है। परंतु, हम इस विचार को किसी अन्य मौके के लिए छोड़ देते हैं।

वर्ष 2024 चुनावों का वर्ष था। तीन बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हुए: भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। भारत में सतारूढ़ दल की तीसरी बार वापसी हुई। एक अलग नेता के नेतृत्व में इंडोनेशिया में सत्तारूढ़ दल जारी रहा। अमेरिका में भी, नए राष्ट्रपति का आगमन हुआ। नए राष्ट्रपति को पद संभाले हुए अभी दो सप्ताह से भी कम समय हुआ है। दुनिया को नीतिगत बदलावों का जल्द ही आभास हो गया है जो वस्तुओं और श्रम की वैश्विक आवाजाही को प्रभावित करेगा।

यूरोप राजनीतिक और आर्थिक दोनों अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। यूरोप के सबसे बड़े आर्थिक *माध्यम*, जर्मनी ने लगातार दो वर्षों तक आर्थिक संकुचन का सामना किया है। राजनीतिक अनिश्चितता भी एक कारक है क्योंकि इस साल फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। फ्रांस में आकस्मिक चुनावों के परिणामस्वरूप हुई गतिविधियों के कारण राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। यूनाइटेड किंगडम में सत्ता परिवर्तन हुआ। लंबे अंतराल के बाद, राजकोषीय दबावों और धीमी अर्थव्यवस्था के बीच लेबर पार्टी सत्ता में आई। सामान्य तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संचरण के कारण, यूरोप बहुत अधिक ऊर्जा लागत के कारण प्रतिस्पर्धात्मकता के दवाब का सामना कर रहा है। इन घटनाक्रमों ने काफी हद तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डलास का वैश्विक आर्थिक गतिविधि सूचकांक महामारी के समय से ही अस्थिर रहा है जो वर्ष 2023 के अंत में धीमा होने लगा है।[1]

कोविड शटडाउन के बाद चीनी अर्थव्यवस्था के फिर से सुचारू होने पर भी आर्थिक विकास दर में तेजी नहीं आई है क्योंकि स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्र में अधिक्षमता और वित्तीय तनाव सामने आए हैं। कुल मांग में कमी के कारण अर्थव्यवस्था या तो अवस्फीति या अपस्फीति मोड में है। घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रोत्साहन के न होने का अर्थ है कि अतिरिक्त श्रम-क्षमता बाह्य बाजारों का रुख कर लेती है। चीन का निर्यात फल-फूल रहा है। 2024 में चीन का व्यापार अधिशेष लगभग एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था।

हाल ही में अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती और अमेरिका में नीतिगत दरों के निर्धारण के संबंध में फेडरल रिजर्व में पुनर्विचार के कारण उभरते बाजारों की मुद्राएं कमजोर हुई हैं। राजकोषीय दबाव और पूर्व की तुलना में कम वास्तविक दरों के कारण कुछ मुद्राओं के मूल्य में अन्य की तुलना में तेजी से गिरावट आई है।

दुनिया भर में कई शेयर बाजार उन्नत स्तरों पर हैं और आर्थिक विकास और उपार्जन संबंधी अनिश्चितताओं के

1 देखें (https://fred.stlousifed.org/series/IGREA.

बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं दिखते हैं। न ही वित्तीय स्थिरता के जोखिमों ने निवेशकों को परेशान किया है, भले ही प्रतिभूतिकरण, लीवरेज ऋण[2] और निजी ऋण[3] के बारे में गंभीर चिंताएं फिर से उभर रही हैं। कुछ मेट्रिक्स के आधार पर, अमेरिकी शेयर बाजार में वर्तमान मूल्यांकन और मनोविचार का स्तर सबसे चरम पर या शीर्ष तीन में से एक हो सकता है।

इस रिपोर्ट में, द फ्यूचर ऑफ यूरोपियन कॉम्पिटिटिवनेस में[4], मारियो ड्रैगी ने लिखा:

"यूरोपीय संघ को अनुकूल वैश्विक वातावरण से भी लाभ हुआ। बहुपक्षीय नियमों के तहत विश्व व्यापार में वृद्धि हुई। अमेरिकी सुरक्षा छत्र से मिले सुरक्षा संबंधी भरोसे ने रक्षा बजट को अन्य प्राथमिकताओं पर खर्च करने का अवसर दे दिया। स्थिर भू-राजनीति की दुनिया में, हमारे पास उन देशों पर बढ़ती निर्भरता के बारे में चिंतित होने की कोई वजह नहीं थी जिनसे हम अपने मित्र बने रहने की उम्मीद करते थे। लेकिन जिन बुनियादों पर हमने निर्माण किया था, वे अब हिल रही हैं। पिछले वैश्विक प्रतिमान क्षीण होते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि का युग बीत चुका है, यूरोपीय संघ की कंपनियों को विदेशों से अधिक प्रतिस्पर्धा और विदेशी बाजारों तक कम पहुंच दोनों का सामना करना पड़ रहा है।"

यह भारत के लिए वैश्विक पृष्ठभूमि है क्योंकि वह विकास की उस गति को स्थिर और कायम रखना चाहता है जो अर्थव्यवस्था ने कोविड के बाद अनुभव की है। तीव्र विश्व व्यापार वृद्धि के युग के बीतने से भारत की निर्यात वृद्धि की संभावनाएं धुंधली हो गई हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, भारत की निर्यात वृद्धि वैश्विक निर्यात वृद्धि पर बहुत अधिक आश्रित रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में घरेलू विकास को बढ़ाने वाले कारक बाह्य क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे।

यूरोपीय प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख भारत के संदर्भ में भी किया जा सकता है। उसमें उल्लिखित अधिकांश चुनौतियाँ भारत पर लागू होती हैं, सिवाय इसके कि भारत एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र है और यूरोपीय महाद्वीप में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यूरोप, कुल मिलाकर, बूढ़ा हो रहा है, लेकिन भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल अधिक युवा है। यह लाभ की स्थिति है, किन्तु इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है।

ड्रेगी रिपोर्ट में एक विशेष उल्लेखनीय बात यूरोपीय प्रतिस्पर्धा के लिए 'चीन की चुनौती' है। भारत के लिए भी यह कम नहीं है। कई टिप्पणीकारों ने हाल ही में इस बारे में लिखा है; चीन पिछले छह वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ा देश बन गया है।[5] एक महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था की बुनियादी ढांचे और निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पैमाने और गुणवत्ता के संबंध में महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने में

---

2 'वॉल स्ट्रीट का जटिल ऋण लाभ 2007 के बाद सबसे तेज गति से बढ़ा', फाइनेंशियल टाइम्स, 10 दिसंबर 2024 (https://www.ft.com/content/5219f962-3499-4928-8c73-5610b7a0109e).

3 'लीवरेज्ड लोन पर डिफॉल्ट 4 साल में सबसे अधिक दर पर पहुंच गया', फाइनेंशियल टाइम्स, 24 दिसंबर 2024 (https://www.ft.com/content/e6ba508c-4612-4b4a-9a6b-ecde6fc91c12).

4 https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en

5 'व्हाट स्केयर्ड फोर्ड्स सीईओ इन चाइना', वॉल स्ट्रीट जर्नल, 14 सितंबर 2024 (https://www.wsj.com/business/autos/ford-china-ev-competition-farley-ceo-50ded46)

भारत को सीमाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र में पॉलीसिलिकॉन, इनगॉट और वेफर्स जैसे उसके प्रमुख घटकों की उत्पादन क्षमता कम है। मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इनगॉट की उत्पादन क्षमता वर्ष 2023 में 2 गीगावॉट से बढ़कर वर्ष 2025 तक पांच गुना होने की उम्मीद है, लेकिन यह देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। देश में कई सौर उपकरण निर्माता चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और संबंधित सेवाओं पर काफी निर्भर हैं। कई उत्पाद क्षेत्रों में एकल-स्रोत पर निर्भरता भारत को आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों, मूल्य उतार-चढ़ाव और मुद्रा जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है। भारत के लिए अवसर कम कर दिए गए हैं।

इसका मतलब है कि घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने, बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना है, जिसकी भारत को प्रतिस्पर्धी और नवोन्वेषी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आवश्यकता है। यह आसान नहीं होगा क्योंकि निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा न केवल अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ बल्कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी है, जो अपने व्यवसाय को अपने तक ही रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह निवेश, घरेलू आपूर्ति-श्रृंखला क्षमता को मजबूती देना और लचीलापन निजी क्षेत्र की ओर से रणनीतिक और दीर्घकालिक सोच की पहचान होगी। जहाँ भी संभव हो, अल्पकालिक लागत संबंधी विचारों से परे जाकर आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों को ढूँढ़ना और उनका पोषण करना होगा।

उपर्युक्त से संबंधित एक अन्य प्राथमिकता जिसके लिए सुविचारित और सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है, वह है जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण। प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और बनाए रखने में सार्वजनिक नीति को ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा किफायतपन की भूमिका को पहचानना होगा। इसका मतलब है कि भारत जीवाश्म ईंधन से अलग ऊर्जा संक्रमण और विविधीकरण के लिए अपना रास्ता तैयार कर रहा है। इस संबंध में, एक ऐसे देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अपने आर्थिक मायने हैं, जो अपना अधिकांश तेल आयात करता है और जिसके पास नवीकरणीय ऊर्जा व कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि, यह बड़ी चुनौतियों को जन्म देता है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। ई-वाहन उत्पादन के आयात का अंश - विशेषकर उन देशों से जिनके साथ भारत का लगातार और वृहद् व्यापार घाटा है - बहुत अधिक है। अल्पावधि में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किस हद तक प्रोत्साहित किया जाता है, इस कारक को ध्यान में रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी और कच्चे माल का स्वदेशीकरण एक अत्यावश्यक कार्य है। अंततः, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के विशाल आकार और सीमित भूमि उपलब्धता को देखते हुए, सार्वजनिक परिवहन व्यवहार्य ऊर्जा संक्रमण के लिए एक अधिक कुशल विकल्प है। इसलिए, राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और स्थानीय सुझावों में निजी परिवहन विकल्पों के टेल-पाइप उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने से परे जाकर इसके उपयोग को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना चाहिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसी प्रोद्योगिकीय प्रगति का लाभ उठाने के लिए भारत के युवाओं को उचित कौशल और शिक्षा की भी आवश्यकता होगी, जिससे यहाँ की जनशक्ति प्रोद्योगिकीय विकास से एक कदम आगे रह सके। इससे रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम या समाप्त भी किया जा सकेगा और यदि संभव हो तो इसे रोजगार बढ़ाने की ताकत के रूप में बदला जा सकेगा। शैक्षणिक संस्थानों और व्यवसायों के बीच सहयोग के लिए इसे 'परंपरागत व्यवसाय' से अलग स्वरूप अपनाने की आवश्यकता होगी। संसाधनों के प्रवाह, विभिन्न प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों के लिए स्वायत्तता का विस्तार करके नवाचार को सुगम बनाया जाना चाहिए, ताकि शेष विश्व से शीर्ष प्रतिभाओं को भारत में आकर्षित किया जा सके। इस मोर्चे पर नीतिगत कार्रवाई पहले से

ही चल रही है, हाल के बजटों में प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें भारत भर के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना और उभरते क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ के वित्तपोषण कार्पस की घोषणा शामिल है।

प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाए बिना प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करना एक अधूरी परियोजना होगी। जैसा कि हमने आर्थिक समीक्षा वर्ष 2023-24 में उल्लेख किया है, कृषि क्षेत्र को पानी पर निर्भर फसलों से भिन्न विविधतापूर्ण फसल उत्पादन के लिए स्वतंत्र, सशक्त और प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सिंचाई क्षेत्र का भी विस्तार करना होगा। कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में बहुत कुछ किया जा सकता है। ओईसीडी द्वारा नवंबर में पेश की गई रिपोर्ट[6] के अवलोकन के माध्यम से किसान सहायता नीतियां लाभकारी हो सकती हैं।

खासकर, विशिष्ट नीतिगत प्रयासों को रेखांकित करना शासन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाने जैसा होगा। "लीक से हट कर चलना" और व्यवसायों को उनके मूल मिशन पर ध्यान केंद्रित करने देना एक महत्वपूर्ण योगदान है जो देश भर की सरकारें नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। देश में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा सकने वाली सबसे प्रभावी नीतियों में से एक उद्यमियों और परिवारों को उनका समय और मेंटल बैंडविड्थ वापस देना है। इसका तात्पर्य विनियमन को महत्वपूर्ण रूप से वापस लेना है। इसका अर्थ है आर्थिक गतिविधियों के सूक्ष्म प्रबंधन को रोकना और जोखिम-आधारित नियमों को अपनाने का संकल्प करना और कार्य करना। इसका मतलब विनियमों के संचालन सिद्धांत को शनिर्दोष साबित होने तक दोषीश से बदलकर 'दोषी साबित होने तक निर्दोष' करने से है। दुरुपयोग को रोकने के लिए नीतियों में प्रचालन संबंधी कई शर्तें जोड़ने से वे समझ से परे हो जाती हैं और विनियमन अनावश्यक रूप से जटिल हो जाते हैं, जिससे वे अपने मूल उद्देश्यों और इरादों से भटक जाते हैं।

उन समाजों के लिए ''लीक से हटना आसान नहीं है, जो अभी भी समुदायों, समूहों और रिश्ते-नातों से घिरे हुए हैं। ये समाज अधिकांशत: पद-संबंध प्रकृति के हैं। विभिन्न संस्थागत ताकतों ने पश्चिमी समाजों में लोगों को बाहर जाने और अजनबियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया। यह प्रक्रिया प्रथम सहस्राब्दी में ही शुरू हो गई थी।[7] परिणामस्वरूप, अजनबियों के साथ व्यवहार करना और उनके साथ नेटवर्क और समुदाय बनाना आवश्यक हो गया। इससे सामाजिक मापदंड अपरिहार्य और आसान हो गए। अजनबियों के साथ व्यवहार करने और उनके साथ संबंध-बनाने के लिए भरोसा करना पड़ता है। लिखित अनुबंध ऐसे विश्वास का आधार बने और इसके बाद अन्य संस्थागत विकास हुए। बहरहाल, भारत जैसे घनिष्ठ और रिश्तेदारी-आधारित समुदायों में, विश्वास का स्तर अभी भी भीतर अधिक है लेकिन बाहर कम है। यह सामजिक मापदंड को बाधित करता है। भरोसे में कमी के कारण विस्तृत सत्यापन, अनुपालन और रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताएं भी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, मोटे तौर पर, पद-संबंध वाले समाज का निर्माण व्यवधान, परिवर्तन और नवाचार के लिए नहीं बल्कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए किया जाता है। यहां तक कि ऐसे समाजों में, स्थानों में और उद्योगों में जहां यह पैटर्न विखंडित है; नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और मापदंड उभर कर सामने आते हैं। नब्बे के दशक में बेंगलुरु में उभरा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र इसकी मिसाल हैं।

---

6 कृषि नीति निगरानी और मूल्यांकन 2024: सतत उत्पादकता वृद्धि के लिए नवाचार' 6 नवंबर 2024 (https://tinyurl.com/zph8e5es).

7 हेनरिक, जोसेफ: 'द वियरडेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड: हाउ द वेस्ट बीकेम साईकोलोजिकली पीक्यूलीयर एंड पार्टीकुलरली प्रोसपेरस'। पेंगुइन बुक्स लिमिटेड किंडल संस्करण

लेकिन, हमें 'लीक से हटना चाहिए' और लोगों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 'परंपरागत व्यवसाय' से आर्थिक स्थिरता तो नहीं लेकिन आर्थिक वृद्धि में ठहराव आने का जोखिम बहुत अधिक रहता है। जी हां, भरोसा एक दो-तरफा रास्ता है और अर्थव्यवस्था में गैर-सरकारी प्रतिभागियों को जताए गए भरोसे को सही साबित करना होता है। वास्तव में, जटिल अनुपालन आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा उन व्यवसायों के प्रयासों से उत्पन्न होता है जो अन्य उद्योगों और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को दूर रखना चाहते हैं। बहरहाल, देश में विश्वास की कमी को दूर करना अत्यावश्यक है और सरकारी एजेंसियों को इस संबंध में एजेंडा तय करना होगा। फिर, यह एक अच्छा विचार है कि भारतीय जनता वर्ष 2047 तक विकसित भारत की राह में चुनौतियों पर काबू पा लेगी और उन्हें अवसरों में बदल देगी।

'बाहरी समाज' पर कम भरोसे का एक अहम पहलू यह है कि पश्चिमी समाजों में विकसित प्रथाएं और नीतियां भारत में लागू नहीं हो सकतीं और उनके सफल होने की संभावना नहीं है। भारत को अपने संदर्भ और इतिहास के अनुकूल अपना रास्ता स्वयं चुनना होगा। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण का प्रत्येक अध्याय जहां भी संभव और आवश्यक हो, सरलीकरण और अविनियमन की बात कहता है, यह उन क्षेत्रों को भी स्वीकार करता है जहां अधिक और/या उचित नियामक हस्तक्षेप आवश्यक है।

उदाहरण के लिए, यह अपेक्षा करना उचित है कि वित्तीय नियामक स्वयं को उन्हीं मानकों पर कायम रखें जिनकी वे विनियमित संस्थाओं से अपेक्षा करते हैं। साथ ही, 'मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास' अध्याय में, हम वित्तीयकरण और आस्ति की कीमतों में उछाल (एसेट प्राइज बबल) के जोखिम के प्रति भी आगाह करते हैं जो अब पश्चिम के लिए स्थानिक हैं। यही कारण है कि भारत के विनियामकों ने निवेशकों के लिए अत्यधिक और वित्तीय रूप से अनर्थकारी सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए जो कुछ उपाय किए, वे केवल प्रणालीगत स्थिरता के लिए नहीं होकर आवश्यक थे। वास्तव में वे कल्याणकारी कदम थे।

इसी तरह, यदि भारत को अपनी युवा आबादी की विशाल संभावना का लाभ प्राप्त करना है, तो उनके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को पोषित करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक प्रमाण इस बात पर बल देते हैं कि अति-प्रसंस्कृत (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों (उच्च वसा, नमक और चीनी या एचएफएसएस) का सेवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को कमजोर करने का एक बड़ा कारक है। इस संबंध में, वैश्विक स्तर पर, स्व-नियमन अप्रभावी रहा है। पैक के ऊपर सख्त लेबलिंग नियमों की आवश्यकता है और उन्हें कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। यह सुझाव देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश के भविष्य की विकास क्षमता इस उपाय पर बहुत अधिक निर्भर करती है। वर्ष 2023 में प्रकाशित डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2006 में भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 37.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई।[8] यह 33% से अधिक की वार्षिक चक्रवृद्धि दर है। यह अस्पष्ट है कि भारत में एचएफएसएस खाद्य पदार्थों के लिए पैक लेबलिंग की स्पष्ट शर्तें हैं या नहीं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सामाजिक क्षेत्र के अध्याय में हमने, स्क्रीन टाइम और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया था। इस बार इस अध्याय में कार्य संस्कृति, जीवनशैली और खान-पान की आदतों का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये कुछ

---

8 'इन अ पिकल: व्हाई इट्स टाइम फॉर एफएसएसएआई टू वेक अप एंड क्रेक द व्हिप', मिंट, 19 मई 2024 (https://www.livemint/com/industry/in-a-pickle-why-it-s-time-for-fssai-to-wake-up-and-crack-the-whip-11716106921958.html)

ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सरकार को कदम उठाने होंगे। साथ ही, जब उच्च शिक्षा की बात आती है, तो अध्याय में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को उन विनियमों द्वारा रोका जाता है जो कथित तौर पर स्वैच्छिक हैं लेकिन प्रभावी रूप से अनिवार्य हैं।

इसके अलावा, इस अध्याय में महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं पर गहराई से पड़ताल की गई है। आर्थिक गतिविधियों में उनकी उत्पादक और संवर्धित भागीदारी को सुविधाजनक बनाना समावेशी विकास नीतियों की अग्नि परीक्षा है। स्त्री-पुरुष युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गरीबों को उनकी आजीविका में सुधार करने और परिधि से चलकर आर्थिक गतिविधि के केंद्र तक जाने के अवसर प्रदान करने के लिए लक्षित सहायता प्रदान की जाएगी। यह सशक्तिकरण के माध्यम से उनकी आय और जीवन स्तर को उन्नत बनाने हेतु रास्ता खोजने के बारे में है। महिलाओं के लिए, देश भर की सरकारों को सुविधाजनक उपाय करने के अलावा श्रम बल में उनकी भागीदारी को रोकने वाली कानूनी और नियामक बाधाओं को खत्म करना होगा। दूसरे शब्दों में, महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने के रास्ते से सरकारों को हट जाना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्र व रोजगार एवं कौशल विकास संबंधी अध्याय पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार और उत्पादन वृद्धि में तेजी लाने के लिए गैर-विनियमन पर बल देते हैं। विशेष रूप से, उद्योग संबंधी अध्याय उन राज्यों के बीच सकारात्मक सहसंबंध को दर्शाता है जो 'व्यापार सुगमता' मापदंडों और औद्योगिक गतिविधि के स्तर पर स्कोर करते हैं। जो राज्य अपने औद्योगीकरण को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। साथ ही, इस अध्याय में एयर कंडीशनर में उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना की सफलता की कहानी की सराहना की गई है, जो सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से सफल स्वदेशीकरण की कहानी है।

बाह्य क्षेत्र के विकास संबंधी अध्याय उन चुनौतियों पर प्रकाश डालता है जिनका भारत को निकट भविष्य में सामना करना पड़ेगा; जैसे प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों का खतरा, जो यूरोपीय संघ ने कार्बन रिसाव से बचने और दुनिया के जंगलों को बचाने के नाम पर शुरू की है। इनमें भारत के निर्यात को प्रतिबंधित करने और चालू खाता घाटा बढ़ाने की क्षमता है, ऐसे समय में जब विदेशी निवेशकों द्वारा सफलतापूर्वक निकासी, कई सरकारों द्वारा निवेश को देश में ही रहने के लिए दिए गए प्रोत्साहन और दुर्लभ मुद्रा (हार्ड करेंसी) में उच्च ब्याज दरों के कारण भारत में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घट रहा है। इसलिए, इस अध्याय में यह सवाल उठाया गया है कि क्या भारत का संधारणीय चालू खाता घाटा पूर्वानुमानित घाटे से कम है। इसका पूंजी निर्माण और निवेश दक्षता या वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात में कमी पर प्रभाव पड़ता है। इस अर्थ में, यह अध्याय बाद के अध्यायों में शामिल घरेलू मुद्दों के संबंध में एक स्पष्ट तर्क प्रदान करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और भारत में रोजगार सृजन हेतु इसके निहितार्थ पर विशेष लेख-रचना हमारी ओर से कुछ अवधारणाओं को सामने रखने का एक साहसिक प्रयास है कि क्या यह प्रौद्योगिकी रोजगार पर अत्यधिक प्रतिकूल एवं विघटनकारी प्रभाव डालेगी। इस लेख में अत्यंत विनम्रता पूर्वक अस्थायी रूप से सुझाव दिया गया है कि कुछ आशंकाएँ गलत हो सकती हैं। यह अध्याय इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है कि क्या दुनिया जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उनके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे तकनीकी समाधान की आवश्यकता है या नहीं। इस प्रकार के प्रश्न पर प्रौद्योगिकीविद् हसेंगे। वे इस बात का प्रतिवाद करेंगे कि प्रौद्योगिकी मनुष्यों की रचनात्मक कौशलता के कारण विकसित होती है और उसके बाद उनका अनुप्रयोग होता है। इसके अलावा, कुछ समाजों में तीव्रतर बढ़ती उम्र को देखते हुए, इसका विकास उनके लिए संभवतः स्वागत योग्य था। यह सभी

देशों के लिए विशेषकर भारत जैसे श्रमशक्ति समृद्ध देश के लिए शायद वैसा नहीं है। इसलिए, उन देशों के नीति–निर्माताओं को यह सवाल करना होगा कि क्या एआई आवश्यक है। यदि उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो इसके लागत और लाभों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। यहां तक कि उन देशों में भी जहां एआई घटती श्रम शक्ति की पूर्ति कर सकता है, एआई की पानी व बिजली की भारी मांग धीरे–धीरे सामने आ रही है, जो नीति–निर्माताओं के लिए काफी हैरानी की बात है। इसलिए, एआई के साथ दुनिया बेहतर है या बदतर, इसका जवाब अब आसानी से नहीं मिल पा रहा है।

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संचरण का विषय, साथ ही उनके अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ और संबंध, आर्थिक समीक्षा के पिछले दो संस्करणों में प्रमुखता से सामने आए हैं। इस बार भी ऐसा ही है। यह विषय कम से कम अगले एक या दो दशक तक हमारे साथ रहेगा। यह एक अन्य क्षेत्र है जहां सरकार जवाबदेही की स्थिति में है, और निजी क्षेत्र कुछ हद तक गौण रहेंगे क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं निजी क्षेत्र की प्राथमिकता नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर, इस बात के पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं कि बिजली के आंतरायिक ऊर्जा स्रोतों पर उच्च व बढ़ती निर्भरता और उच्च ऊर्जा लागतों के बीच गहरा संबंध है। वास्तव में, आकस्मिकता की दिशा संभवत: पूर्ववर्ती से उत्तरवर्ती की ओर है और यह जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन में तीव्र और गहरी गिरावट के कारणों में से एक है, क्योंकि उद्योग, उच्च ऊर्जा लागत का हवाला देते हुए अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो रहे हैं। शोध[9] में कहा गया है कि कम कार्बन वाले संसाधन – जिनमें परमाणु ऊर्जा, बायोएनर्जी और कार्बनडाईआक्साइड को ग्रहण करने वाले प्राकृतिक गैस संयंत्र शामिल हैं – बिजली उत्पादन के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की लागत को घटाने में मदद करते हैं, क्योंकि इन संसाधनों के बिना कार्बनडाईआक्साइड की सीमा शून्य के करीब पहुँचने के कारण लागत तेजी से बढ़ती है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग ऊर्जा परिवर्तन की गारंटी देती है, जैसा कि प्रोफेसर माइक हल्म पिथिली ने अपनी पुस्तक का शीर्षक दिया है, 'क्लाइमेट चेंज इज नॉट एवरीथिंग'।

जैसा कि हमने इस प्रस्तावना में पहले उल्लेख किया है– और अब इसके निष्कर्ष पर पहुँचने का समय आ गया है – ऊर्जा संचरण योजनाओं को भू–राजनीतिक सुभेद्यताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए और महत्वपूर्ण आयातों के संबंध में बाहरी स्रोतों पर भारत की निर्भरता को बढ़ाने से बचना चाहिए। इस संबंध में कार्यनीतिक विचारशीलता की आवश्यकता है। पश्चिम की दो मनोग्रस्तियाँ; पानी व बिजली की खपत करने वाला एआई और ऊर्जा संचरण – एक–दूसरे के साथ अच्छी तरह मेल नहीं खाते हैं। एक को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊर्जा संचरण को ही छोड़ना होगा क्योंकि पश्चिम (विशेष रूप से यूरोप) अपने ऊर्जा मिश्रण में पवन और सौर ऊर्जा को जितना अधिक अपनाएगा, चीन में कोयले की खपत उतनी ही अधिक होगी। दोनों के बीच संबंध इस प्रकार है :– समग्र ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी के साथ महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा की आवश्यकता बढ़ जाती है। चीन इस सामग्री के उत्पादन या प्रसंस्करण पर हावी है। प्रसंस्करण के लिए सस्ती बिजली की आवश्यकता होती है। अन्यथा, ये इनपुट महंगे होंगे, जिससे यूरोप के लिए ऊर्जा संक्रमण पहले से भी अधिक महंगा हो जाएगा। सस्ती बिजली केवल कोयले से चलने वाले तापीय संयंत्रों से ही संभव है। इसलिए एड कॉनवे ने लिखा है[10] कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह जटिल पारस्परिक प्रभाव भारत के लिए एक बात स्पष्ट करती है। इसे उत्सर्जन शमन की तुलना में अनुकूलन पर अब तक जितना ध्यान दिया है, उससे कहीं अधिक ध्यान देना होगा। जलवायु और पर्यावरण संबंधी अध्याय का

9 सेपुलवेडा एट अल., (2018): द रोल आफ फर्म लो–कार्बन इलेक्ट्रीसिटी रिसोर्सेज इन डीप डीकार्बोनैजेशन ऑफ पावर जेनेरेशन, जूल 2, 2403–2420, 21 नवंबर, 2018, 2018 एल्सेवियर इंक (https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.08.006)

10 एड कॉनवे: 'द मोस्ट होपफुल चार्ट इन द वर्ल्ड', 19 दिसंबर 2024 (https:/.edconway.substack.com/p/the-most-hopeful-chart-in-the-world)

केंद्रीय विषय यही है।

पहला और पाँचवाँ अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सन्निकट अवधि और मध्यावधि के दृष्टिकोण से संबंधित है। पहले अध्याय में वैश्विक विकास और जोखिम कारकों पर सामान्य रूप से की जाने वाली चर्चा की तुलना में अधिक विस्तारपूर्वक विमर्श किया गया है। वैश्विक स्थिति को देखते हुए यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। मध्यम-अवधि का दृष्टिकोण इस प्रस्तावना में उल्लिखित कई मुद्दों की विस्तृत जाँच है - और फलतः, गैर-विनियमन के सभी उपायों को क्रियाशील करते हुए घरेलू आर्थिक इंजन को गति देने की आवश्यकता है। जैसा कि सभी आर्थिक समीक्षाओं में परंपरा है, पहले अध्याय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक आर्थिक विकास दर के प्रति हमारे दृष्टिकोण को व्यक्त किया जाता है। मैं इसे यहाँ प्रकट नहीं करने जा रहा हूं ताकि आप आगे के पृष्ठों पर भी अपनी दृष्टि डालें। आप संबंधित आंकड़ों को पहले अध्याय के अंत में देख सकते हैं। वृद्धि के अनुमान के पीछे का मूल तत्व उस विचार के अनुरूप है जिसे सरकार और वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय लक्ष्यों के संबंध में पिछले पांच वर्षों में अपनाया है: यथार्थवादी बनें और जो है उससे बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करें। इस अवधि में सार्वजनिक वित्त को पटरी पर लाने में शानदार प्रगति इस दृष्टिकोण का प्रमाण है।

आर्थिक समीक्षा का यह संस्करण सरकार की क्षमता संबंधी मुद्दों से संबंधित नहीं है। जुलाई, 2024 में प्रकाशित पिछले संस्करण में ऐसा था। इन विकासात्मक गतिविधियों के प्रति अनुक्रिया और बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों के बीच सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर प्रगति करने के लिए सरकार की क्षमता और सामर्थ्य की मांग आजादी के बाद से हमारे द्वारा अनुभव की गई किसी भी बात से भिन्न होगी। उस मांग को पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर विकास पथ पर है। वृहद आर्थिक परिदृश्य बेहतर स्थिति में है। चूंकि देश का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपनी आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना है, इसलिए घरेलू कॉर्पोरेट और वित्तीय क्षेत्रों में मजबूत बैलेंस शीट की वजह से उसे मदद मिल रही है। लेकिन, वैश्वीकरण वापसी (रिट्रीट) की स्थिति में है। इसलिए, अगले दो दशकों में वृद्धि के औसत को बढ़ाने के लिए गैर-विनियमन प्रेरकों के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करना होगा। जैसा कि स्पार्टन्स स्पष्ट रूप से मानते थे, ''शांतिकाल में आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, युद्ध में आपको उतनी ही कम क्षति होगी''। यह आर्थिक सर्वेक्षण कुल मिलाकर उसी के बारे में है, या यूं कहें कि हमें इसीलिए इस पर विश्वास है।

मुझे आशा है कि इस प्रस्तावना ने आपको इस आर्थिक समीक्षा की झलक दी होगी और इसमें आगे क्या दिया गया है, इसके बारे में और अधिक जानने की आपकी इच्छा बढ़ी होगी। मैं इस दस्तावेज में व्यक्त विचारों और त्रुटियों, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी हूं। कृपया हमें बताएं कि आप हमारे विचारों के बारे में क्या सोचते हैं और त्रुटियाँ, यदि हों तो उन्हें भी इंगित करें। हम वादा करते हैं कि हम हर बार बेहतर होते जाएंगे।

हमेशा की तरह, मिलकर विचार-विमर्श करना आनंददायी और यज्ञ की भांति है। परिवर्तन को मूर्त रूप देना ही साधना है।

(वी. अनंत नागेश्वरन)
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय, भारत सरकार
जनवरी 31, 2025

आभारोक्ति

आर्थिक समीक्षा 2024–25 सामूहिक प्रयास का परिणाम है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन के अवलोकन और विचार बहुत मूल्यवान रहे हैं। सर्वेक्षण में माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और सचिव (राजस्व) श्री तुहिन कांता पांडे, सचिव डीईए श्री अजय सेठ, सचिव (व्यय) डॉ. मनोज गोविल, सचिव (दीपम) श्री अरुणीश चावला और सचिव (वित्तीय सेवाएं) श्री एम. नागराजू के सहयोग का हृदय से आभार व्यक्त किया गया है।

आर्थिक प्रभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से समीक्षा में योगदानकर्ताओं में शामिल हैं: चांदनी रैना, एंटनी सिरिएक, अनुराधा गुरु, कोकिला जयराम, धर्मेंद्र कुमार, हरीश कुमार कलेगा, दीपिका श्रीवास्तव, गुरविंदर कौर, नेहा सिंह, वेंकट हरिहरन आशा, मेघा अरोड़ा, ममता, श्रुति सिंह, गार्गी राव, रितिका बंसल, ईशा स्वरूप, प्रद्युत कुमार पाइन, मोहम्मद आफताब आलम, राधिका गोयल, मंजू, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, मृत्युंजय कुमार, अजय ओझा, सलोनी भूटानी, दीपदुयति सरकार, हेमा राणा, रोहित कुमार तिवारी, सोनाली चौधरी, भारद्वाज आदिराजू, मीरा उन्नीकृष्णन, आकाश पुजारी, सुरभि सेठ, तनिका लूथरा, विशाल गौरी, रितेश कुमार गुप्ता, मुना साह, बृजपाल और अधिकारियों के निजी कर्मचारी।

समीक्षा कार्य को आर्थिक कार्य विभाग के कई अधिकारियों के योगदान और विचारों से लाभ मिला है: राजीव मिश्रा, सोलोमन अरोकिराज, बलदेव पुरुषार्थ, सैयद जुबैर नकवी, सीमा जोशी, अपराजिता त्रिपाठी, हरीश यादव, कुणाल बंसल, चंचल सी सरकार, कपिल पतिदर।

उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों ने अपने–अपने क्षेत्रों में योगदान दिया, इनमें शामिल हैं: इश्तियाक अहमद, लालसंगलूर, नीलांभुज शरण, पियुश श्रीवास्तवा, योगेश सुरी, इंद्राणी कौशल, प्रीति नाथ, राजश्री रे, समीर कुमार, डॉ. कामखेनथांग गुइटे, कुशुम मिश्रा, ए. श्रीजा, एम सुब्रामन्यम, अनुजा बापत, डॉ. बिजया कुमार बेहेरा, शेफाली ढींगरा, डॉ. सी. वनलालरामसांगा, डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, सोनिया पंत, गाईत्री नायर, अनुपम प्रकाश, एमजी जयश्री, जयपाल, साराह मुजीब, अमन गर्ग, श्वेता कुमार, अभिशेक आचार्य, देवी प्रसाद मिश्र, अनुपा नायर, सुरजीत कार्तिकेयन, मनोज मधोलिया, श्वाती सिंघला, अनुश्री राहा, शालिनी गुप्ता, रबी रंजन, आशीष शिंदे, नितिशा मान, राजकुमार, पीके आर्या, रेशमा राजीवन, कामिल केपीएस भुल्लर, पारुल जैन, चिराग रावत, आर.एस. महेश कुमार, श्रीजीत ओपी, मुकेश कुमार सिंह, राजेश कुमार, विशाल विश्वनाथ नायर, मृत्युंजय झा, पूर्णीमा एम, जे. रमेश कुमार, रूचि शर्मा, पुनीत भाटिया, अनन्यब्रत मौलिक, कुशवंत कुमार, जे. राजेश कुमार, सुनीता यादव, इम्तियाज अहमद, उन्मना सारंगी, विजय राणा, मोहित वर्मा, चितवन सिंह ढिल्लोन, शोभित श्रीवास्तव, दीपक कुमार मीना, रियाज अहमद खान, स्वाति सेनन, रिमझिम टी. देसाई, सोनम चौधरी, मयंक त्रिवेदी, ए.सी. मैथ्यू, ए.आर. रॉय, अनु वर्मा, शशि रंजन, खुशबू, अमित कुमार, डॉ. रबिन्द्र कुमार पाणिग्राही, स्वेता सत्या।

हमें कई विशेषज्ञों, उद्योग निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं से भी सहायता मिली जिनमे सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, आईएफएससीए, गिफ्ट सिटी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, सीबीआईसी, एनआईयूए, नैसकॉम, सी–डीओटी, ओएनडीसी, एनएचबी, नाबार्ड, विश्व बैंक के कर्मचारी, अरूण रॉय, डा. भरत रामास्वामी, डॉ. एन आर भानुमूर्थी, डॉ. एम सुरेश बाबु, डॉ. तीर्थंकर पटनायक, पी. सेन्थिल कुमार, एस

विश्वनाथन, प्रिया वेदावल्ली, नीलांजन सरकार, शैलेंदर स्वामीनाथन, स्वेता सिंघारो, डॉ. प्रतिभा नारायणन, टी. ए. पद्मनाभन, संदीप सचदेवा, डॉ. अमित कपूर, भुवना आनंद, शुभो रॉय, डॉ. विन्नी जौहरी, रवि वेंकटेशन, दिग्विजय सिंह नेगी, शिरीष जोशी और डॉ. बीना विग्नेश्वरन

मनोज सहाय, अपर्णा भाटिया, जसबीर सिंह, सुश्रुत सामंत, अजय कुमार सिंह, दलीप कुमार, पंकज कुमार, दवेंद्र कुमार, नवनीत पाठक, राहुल गोयल और डीईए के अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा सक्षम प्रशासनिक सहयोग दिया गया है।

समीक्षा का हिंदी अनुवाद आर्थिक कार्य विभाग के हिंदी अनुभाग के शिशिर शर्मा, हरीश सिंह रावत, रजनीश कुमार, अनुपम आर्या, समता रानी, बबिता गुंज्याल, झंटू कुमार मंडल, विनय कुमार, माया मीना और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से विभा मित्तल, सतेंद्र राठी, डॉ. गौतम शर्मा, मनीष भटनागर, मनोज कुमार, राघवेंद्र पांडे, दिवाकर शुक्ला, रविशंकर मीना, डॉ धमेंद्र कुमार ने किया। आर्थिक समीक्षा के हिंदी संस्करण का टंकण कार्य जिया लाल मैठाणी और संजय प्रसाद, मुद्रण निदेशालय, मिंटो रोड द्वारा किया गया है।

समीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों की पेज सेटिंग सिग्नेचर प्रिंटर्स के इज्जुर रहमान, दीपक अग्रवाल और दिव्यांश द्वारा की गई है। इसके अलावा, समीक्षा के लिए कवर पेज इज्जुर रहमान द्वारा डिजाइन किया गया है।

आर्थिक समीक्षा इसकी तैयारी में शामिल सभी लोगों के परिवारों के प्रति उनके धैर्य और सहयोग के लिए गहरा आभार व्यक्त करता है।

वी. अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

संकेताक्षर

एए	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण/न्यायनिर्णायक प्राधिकारी
एएएम	आयुष्मान आरोग्य मंदिर
एएवाई	अंत्योदय अन्न योजना
एबी पीएम–जेएवाई	आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
एबीसी	अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
एबीडीएम	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
एबीएचए	आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता
एबीएस	स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग
एडीयूडब्लू	असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस
एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ
एजीआई	कृत्रिम सामान्य बुद्धिमता
एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआईएफ	कृषि अवसंरचना निधि
एआईएम	अटल नवाचार मिशन
एएमएफआई	एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया
एएमआई	कृषि विपणन अवसंरचना
एएमआरयूटी	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
एएनबीसी	समायोजित नेट बैंक ऋण
एपीआई	सक्रिय औषधीय तत्व
एपीएमसी	कृषि उपज मंडी समिति
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एआरसी	ऑटोनमस रिजनिंग कैपेबिलिटी
एएसआई	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
एएसयूएसई	असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण
एटीएमए	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी
एयूसी	अभिरक्षाधीन आस्तियाँ
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां
एयूएससी	उन्नत अल्ट्रा–सुपर–क्रिटिकल
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क
बीसीजी	बैसिल कैलमेट गुएरिन
बीएफएसआई	बैंकिंग वित्तीय सेवाएँ बीमा
बीएफटी	बेयर फुट टेक्नीशियन
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीआईएस	बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स
बीओपी	भुगतान संतुलन

बीपीएल	गरीबी रेखा के नीचे
बीपीएनआई	भारतीय स्तनपान संवर्धन नेटवर्क
बीपीओ	बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
बीआरएपी	व्यापार सुधार कार्य योजना
बीआरआर	व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट
बीआरएसआर	व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट
बीटीएस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन
सीएबी	चालू खाता शेष
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजी	नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सीएजीआर	कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट
कैम्पा	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
सीएपीई अनुपात	चक्रीय रूप से समायोजित मूल्य-से-आय अनुपात
सीएएसईएल	शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के लिए सहयोगात्मक
सीबीएएम	कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म/कार्बन सीमा समायोजन तंत्र
सीबीआईएस	क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम
सीसीआरपी	सी-डॉट सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम
सीसीएस	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
सीसीयू	कार्डियक केयर यूनिट
सी-डॉट	टेलीमेटिक्स विकास केंद्र
सीडी	कॉर्पोरेट देनदार
सीई	पूंजीगत व्यय
सीईओबीई	ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर
आईसीईआरटी	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल
सीईटी-1	कॉमन इक्विटी टियर-1
सीएफपीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीजीए	लेखा महानियंत्रक
सीजीएफएसएसडी	कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीजीएस	ऋण गारंटी योजना
सीजीएस-एनपीएफ	नीति संक्षिप्त ई-एनडब्ल्यूआर-आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण
सीजीएसएस	स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
सीजीटीएमएसई	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास
सीएचएएमपीआईओएनएस (चौंपियंस)	राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने हेतु आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और उनका सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सीएचसी	कस्टम हायरिंग सेंटर

सीएचई	वर्तमान स्वास्थ्य व्यय
सीआईआरपी	कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया
सीएलएफ	क्लस्टर लेवल फेडरेशन
सीएलयू	भूमि उपयोग में परिवर्तन
सीएमए	पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करने वाला पक्षकारों का सम्मेलन
सीओपी	कॉन्फरेंस ऑफ द पार्टीज
सीएफसी	कॉमन सुविधा केंद्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीपीएसयू	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल)	क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीआरओपीआईसी	फसलों के वास्तविक समय अवलोकन और तस्वीरों का संग्रह
सीआरपी	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीआरजेड	तटीय विनियमन क्षेत्र
सीएससीएएफ	जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन ढांचा
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसडीसीआई	भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद
सीएसई	विज्ञान और पर्यावरण केंद्र
सीएसआईआरटी	कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल क्षेत्रीय
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
सीएसआर	कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
सीवीडी	कार्डियोवैस्कुलर डिजीज
सीडब्ल्यूपीपी	सामुदायिक जल शोधन संयंत्र
सीडब्ल्यूएस	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति
सीडब्लूएसएन	चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स
दा जगुआ	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
डीएएचडी	पशुपालन और डेयरी विभाग
डे-एनआरएलएम	दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीबीएन	डिजिटल भारत निधि
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीओएस	डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस
डीडीयूजीजेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीएफसी	डेडिकटेड फ्रेट कॉरीडोर
डीएफआई	किसानों की आय दोगुनी करना

डीएफआई	विकास वित्त संस्थान
डीजीसीए	नागरिक विमानन महानिदेशालय
डीजीएफएसएएलआई	महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईईटी	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
दीक्षा	डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग
डीआई	ड्रग इंटरमीडिएट्स
डीएमपी	आपदा प्रबंधन योजना
डीओजीई	डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी
डीपीआई	डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
ड्रे	विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा
डीटीई	बहुत यथार्थवादी और व्यावहारिक.
म-बीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट
ईसीसीई	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
ईसीईएच	ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र
ईसीएचएस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ईडीपीएमएस	निर्यात डाटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली
ईईआई	क्षेत्रीय विस्तार शिक्षा संस्थान
ई-केवाईसी	इलेक्ट्रॉनिक - अपने ग्राहक को पहचानें
ईएमसी	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर
ईएमडीई	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ई-नाम	इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
ई-एनडब्ल्यूआर	इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीआर	विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी
ईपीयू	आर्थिक नीति अनिश्चितता
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ई.टीएस	उत्सर्जन व्यापार प्रणाली
ईयूडीआर	यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन
ईवी	विद्युत वाहन
एफएडीए	फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एफएआर	पूर्णतः सुलभ मार्ग
एफसीए	विदेशी मुद्रा आस्तियां/परिसंपत्ति
एफसीएनआर	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता
एफडी	राजकोषीय घाटा

एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफएफआर	संघीय निधि दर (फेडरल फंड्स रेट)
एफआईडीएफ	मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि
एफएलएफपीआर	महिला श्रम बल भागीदारी दर
एफएलएन	मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता
एफएमसीजी	फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान)
एफएमजी	फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट
एफएमआई	वित्तीय बाजार अवसंरचना
एफएनएचडब्ल्यू	भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता
एफओएमसी	फेडरल ओपन मार्केट कमेटी
एफओपीएल	फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग
एफपीसी	किसान उत्पादक कंपनियाँ
एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ	किसान विकास उत्पादक संगठन
एफपीएस	उचित मूल्य की दुकान
एफआरईई-एआई	फ्रेमवर्क फोर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ओएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एफआरईपीएस	वित्तीय, भू-संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौता
एफटीएल	फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफवाई	वित्त-वर्ष
जीएएमई	ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप
जीसीए	सकल फसल क्षेत्र
जीसीसी	ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर
जीसीसी	खाड़ी सहयोग परिषद
जीसीएफ	ग्रीन क्लाइमेट फंड
जीसीआई	वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक
जीसीपी	ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
जीसीटी	गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएपीपी	ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लनेट
जीईसी	हरित ऊर्जा गलियारा

जीईएफ	भू-आर्थिक विखंडन
जीईएम	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
जीईपीयू	वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीएफसी	वैश्विक वित्तीय संकट
जीएफसीएफ	सकल स्थायी पूंजी निर्माण
जीएफसीआई	वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक
जीएचई	सरकारी स्वास्थ्य व्यय
जीएचजी	ग्रीन हाउस गैस
जीआईएफटीसी-आईएफएससी	गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
जीआईआई	ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
जीएलसी	ग्राउंड लेवल क्रेडिट
जीएमपी	गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसिस
जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्तियां
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीपी	जेंडर पॉइंट पर्सन्स
जीपीआर	भू-राजनीतिक जोखिम
जीआरसी	जेंडर रिसोर्स सेंटर्स
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीएसवीए	सकल राज्य योजित मूल्य
जीटीआर	सकल कर राजस्व
जीवीए	सकल मूल्य वर्धित
एचसीईएस	घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण
एचडीआई	मानव विकास सूचकांक
एचईआई	उच्च शिक्षा संस्थान
एचएफआई	उच्च आवृत्ति संकेतक
एचएससी	हाई-स्पीड कॉरिडोर
एचएसएन	नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
एचडब्ल्यूसी	स्वास्थ्य कल्याण केंद्र
आईएएस	कृषि स्थिरता सूचकांक
आईएवाई	इंदिरा आवास योजना
आईबीसी	दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता
आईबीयू	आईएफएससी बैंकिंग इकाइयाँ
आईसीसीसी	एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र
आईसीईटी	महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका-भारत पहल
आईसीआईसीआई	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

आईसीआरआईईआर	भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईडीबीआई	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीएफसी	इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी
आईईए	अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
आईईसी	आयातक-निर्यातक कोड
आईईओ	स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय
आईएफसीआई	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
आईएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आईजीबी	भारत में सरकारी बांड
आईआईई	भारतीय उद्यमशीलता संस्थान
आईआईएफसीएल	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
आईएलओ	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएनआर	भारतीय रुपया
इनवीआईटी (इन्विट्स)	इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट
आईओएमटी	इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स
आईओटी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आईपी	बौद्धिक संपदा
आईपी	ब्याज भुगतान
आईपीडीएस	एकीकृत विद्युत विकास योजना
आईपीओ	प्रारंभिक सार्वजानिक प्रस्ताव
आईआर	भारतीय रेल
आईआरबी	स्वतंत्र नियामक निकाय
आईआरईएनए	अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी
आईएस	ब्याज अनुदान
आईटी	सूचान प्रौद्योगिकी
आईटीए	अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन
आईटीईएस	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जेजेएम	जल जीवन मिशन
जेएसएस	जन शिक्षण संस्थान
केसीसी	किसान कॉल सेंटर
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केआईएलए	केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान
केएलईएमएस	पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री, और सेवाएं

किमी	किलोमीटर
केपीआई	मुख्य निष्पादन संकेतक
केएसआई	मुख्य प्रारंभिक सामग्री
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलबीएसएपी	स्थानीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजनाएँ
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एलआईएफई	पर्यावरण के लिए जीवनशैली
एलएलएम	लार्ज लैंग्वेज मॉडल
एलएमए	श्रमिक गतिशीलता समझौता
एलएमटी	लाख मीट्रिक टन
एलएसए	लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज
महाएफपीसी	महा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
मैत्री	ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियन
एमएएस	मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमएफएन	मोस्ट फेवर्ड नेशन
एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएचक्यू	मानसिक स्वास्थ्य क्वोशेंट
मिष्टी	तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल
एमआईएसएस	संशोधित ब्याज अनुदान योजना
एमएल	मशीन लर्निंग
एमएलडी	प्रति दिन दस लाख लीटर
एमएम	मुद्रा गुणक
एमएमएफ	मानव निर्मित फाइबर
एमएमएलपी	मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
एमएमपीए	प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते
एमएनआरई	नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय
एमओई	शिक्षा मंत्रालय
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओईएस	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
एमओएचयूए	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
एमओएलई	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन

एमओवीसीडीएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमपीसी	बहुउद्देश्यीय केंद्र
एमपीसीई	मासिक प्रति व्यक्ति व्यय
एमआर	खसरा रूबेला
एमआरओ	अनुरक्षण मरम्मत और ओवरहाल
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
एमएसई-सीडीपी	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम
एमएसईएफसी	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसयू	मोबाइल स्टोरेज यूनिट
एमटीपीए	मिलियन टन प्रति वर्ष
एमवीए	मेगा वोल्ट-एम्पीयर
एनएबीएआरडी (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएबीसीओएनएस.	नाबार्ड परामर्श सेवाएँ
एनबीएफआईडी	राष्ट्रीय वित्त पोषण और अवसंरचना विकास बैंक
एनएबीएल	नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग ऐंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज
एनएसीएच	राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनएएलएसए	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
एनएपी	राष्ट्रीय अनुकूलन योजना
एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
एनपीआई	न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इन्टरेस्ट
एनएपीएस	राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना
एनएक्यूआईएम	राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम
एनएएसएससीओएम (नैसकॉम)	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
एनसीएपी	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
एनसीडी	गैर-संचारी रोग
एनसीएफ-एफएस	नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण
एनसीक्यूजी	नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य
एनसीआरएफ	नेशनल क्रेडिट फरेमवर्क
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनडीएफ	नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड
एनडीएमपी	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
एनडीआर	गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां

एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनईईआर	नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
नीट–यूजी	राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ख्र स्नातक
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनएफडीपी	राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनजीआरबीसी	उत्तरदायी कारोबार संचालन पर राष्ट्रीय दिशा–निर्देश
एनएच	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनआईडीएचआई (निधि)	नवाचारों के विकास और उपयोग के लिये राष्ट्रीय पहल
एनआईईएसबीयूडी	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान
एनआईआईएफ	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि
एनआईएम	निवल ब्याज लाभ
एनआईपी	नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन/राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम
निपुण	नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ऐंड न्यूमेरेसी
एनआईटीआई	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था
एनआईयूए	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान
एनएमसी	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
एनएमपी	राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
एनएमएसए	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
एनएमएसएच	राष्ट्रीय सतत आवास मिशन
एनपीए	अनर्जक आस्ति
एनपीसीडीसीएस	कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
एनआरआर	राजस्व प्राप्तियाँ (केंद्र को निवल/शुद्ध)
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एनएसआईएल	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क
एनएसटीआई	राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान
एनटीसी	कर राजस्व (केन्द्र को निवल/शुद्ध)
एनटीएम	गैर टैरिफ उपाय/गैर प्रशुल्क उपाय
एनटीपीसी	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

एनटीटीएम	राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन
ओबीआईसीयूएस	ऑर्डर बुक, सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण
ओसीईएन	ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क
ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्ति
ओडीएल	मुक्त दूरस्थ शिक्षा
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएमओ	खुले बाजार परिचालन
ओएनडीसी	ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स
ओएनओआरसी	एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड
ओओपीई	आउट–ऑफ–पॉकेट एक्स्पेंडिचर
ओपीवी	ओरल पोलियो वैक्सीन
ओआरआर	स्वयं की राजस्व प्राप्तियां
ओएसएच	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य
ओटीआर	स्वयं कर राजस्व
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
पीएडीओएस	लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं
पीएएचओ	पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन
परख	परफोर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट
पीएटी	कर के बाद लाभ
पीएवाईजी (पे–एज–यू–गो)	उपयोगानुसार भुगतान करो
पीबीएमसी	निष्पादन आधारित अनुरक्षण संविदा
पीबीएस	पॉप्युलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग
पीडी	प्राथमिक घाटा
पीडीएमसी	प्रति बूंद अधिक फसल
पीडीओटी	प्रस्थान–पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएफसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीएफआरडीए	भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएचएच	प्राथमिकता वाले परिवार
पीआईबी	प्रेस सूचना ब्यूरो
पीकेवीवाई	परम्परागत कृषि विकास योजना
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएलआई	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन
पीएलआईएसएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

पीएम जनमन	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान
पीएम पोषण	प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण
पीएम श्री	उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल
पीएमएवाई–जी	प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण
पीएमएवाई–यू	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी
पीएमबीजेके	प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र
पीएमएफबीवाई	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
पीएमएफएमई	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण
पीएमजीदिशा	प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
पीएमजीकेएवाई	प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमआई	क्रय प्रबंधक सूचकांक
पीएमजेजेबीवाई	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएम–किसान	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि
पीएमकेएसके	प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केन्द्र
पीएमकेएसवाई	प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना
पीएमकेएसवाई	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएम–कुसुम	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
पीएमकेवीवाई	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
पीएम–एमआईटीआरए	प्रधान मंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र)
पीएम–एमकेएसएसवाई	प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना
पीएमएमएसवाई	प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीपीपी	सार्वजनिक–निजी भागीदारी
पीआरएएसएचएडी (प्रसाद)	तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान
पीआरआई	शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन
पीएसएल	प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को ऋण
पीवी	फोटोवोल्टिक सेल
पीवीटीजी	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
क्यूआईपी	क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स
आरएंडडी	अनुसंधान एवं विकास
आर–डी	अनुसंधान और विकास
आरएडी	वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
आरएएस	पुन:परिसंचरण जलीय कृषि प्रणालियाँ
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीए	रिवर सिटीज एलायंस

आरसीबी	ग्रामीण सहकारी बैंक
आरडी	राजस्व घाटा
आरई	राजस्व व्यय
आरईसी	अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र
आरईईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरईआईटी	भू-संपदा निवेश निकाय
आरईआरए	भू-संपदा विनियमन अधिनियम
आरई	विनियमित संस्थाएं
आरईएस	अक्षय ऊर्जा स्रोत
आरएफआई	ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ
आरआईए	विनियामक प्रभाव आकलन
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरओएससीटीएल	राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों में छूट
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसए	पुनर्गठित मानक अग्रिम
आरएसबीवाई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आरटीए	क्षेत्रीय व्यापार समझौता
आरटीपी	रिजर्व ट्रेंच पोजीशन
आरवीएसएफ	पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं
एसएजीवाई	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एसएएमएआरटीएच (समर्थ)	स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब
एसएआरटीएचएक्यू	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति
एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन
एसबीएम-जी	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण
एसबीएम-यू	स्वच्छ भारत मिशन - शहरी
एससी	सुपर-क्रिटिकल
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एसडी 2.0	स्वदेश दर्शन
एसडीजी	संधारणीय विकास लक्ष्य
एसडीजीसीएसी	एसडीजी समन्वय और त्वरण केंद्र
एसडीजीसीसी	एसडीजी समन्वय केंद्र
एसडीआर	विशेष आहरण अधिकार
एसईएल	सामाजिक और भावनात्मक अधिगम
एसएफआई	आत्मनिर्भर भारत

एसजीआरबी	सॉवरेन ग्रीन बांड
एसएचसी	उप-स्वास्थ्य केंद्र
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईए	एसबीआई इंटेलिजेंट असिस्टेंट
एसआईआई	सेफ इन इंडिया फाउंडेशन
एसआईआईसी	स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
एसआईपी	सुनियोजित निवेश योजना
एसआईएसएफएस	स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम
एसएलसीआर	स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमएएम	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन
एसपीएस	स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय
एसआरआई	सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन (सघन धान प्रणाली)
एसआरएलएम	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एसएससी	सेक्टर स्किल काउंसिल
एसएसई	सामाजिक क्षेत्र व्यय
एसटीएआरएस	स्ट्रेंगथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स
एसटीईएम	विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित
एसटीएमसी	अल्पावधि अनुरक्षण संविदा
एसटीआरवाई	ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण
एसयूएल	सौर ऊर्जा लैंप
एसडब्ल्यूएवाईएएम	स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स
टीबीटी	व्यापार में तकनीकी बाधाएँ
टीडी	कर न्यागमन/कर अंतरण
टीई	कुल व्यय
टीईयू	बीस-फुट समतुल्य इकाइयाँ
टीएचई	कुल स्वास्थ्य व्यय
टीओपी	टमाटर, प्याज और आलू
टीपीडीएस	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
टीपीयू	व्यापार नीति अनिश्चितता
टीआरईडीएस	ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम
टीटीएचसीएस	व्यापार, परिवहन, होटल, संचार एवं प्रसारण सेवाएं
टीटीटी	टिम टिम तारे
टीवीईटी	तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण
यूएएन	यूनिवर्सल खाता संख्या
यूएपी	उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म

यूडीएएन (उड़ान)	उड़े देश का आम नागरिक
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईपी	यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूएलआई	एकीकृत ऋण अन्तरापृष्ठ
यूएलएलएएस	समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम्बोध
यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
यूएनसीटीएडी-ट्रएइनएस	यूएनसीटीएडी व्यापार विश्लेषण सूचना प्रणाली
यूएनईए	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूएनईएससीएपी	संयुक्त राष्ट्र-एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन
यूएनआईडीओ	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
यूपीएफ	अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड
यूपीआई	एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ
यूआर	बेरोजगारी दर
यूआरएमपी	शहरी नदी प्रबंधन योजना
यूएस	यूजुअल स्टेटस
यूएससी	अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल
यूएसडी	यूनाइटेड स्टेट डॉलर
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वीजीएफ	व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण
वीओ	ग्राम संगठन
डबल्यूएएसएच (वॉश)	जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य
डब्ल्यूईई	महिला आर्थिक सशक्तिकरण
डब्ल्यूएफईपी	महिला उद्यमी वित्तीय सशक्तिकरण कार्यक्रम
डब्ल्यूईओ	वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
डब्ल्यूएफपी	विश्व खाद्य कार्यक्रम
डब्लूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआईएनडीएस	मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
डब्ल्यूपीआर	श्रमिक जनसंख्या अनुपात
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
डब्ल्यूटीयूआई	विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक
यस-टेक	प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली
वाईओवाई	वर्षानुवर्ष/साल दर साल

तालिकाओं की सूची

तालिका सं.	तालिका	पृष्ठ सं.
तालिका II.1	सामान्य जीडीपी अनुपात के लिए बाजार पूंजीकरण (प्रतिशत)	55
तालिका III.1	सी.बी.ए.एम. निर्यात मूल्य में भारत का एक्सपोजर (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	90
तालिका IV.1	प्याज और टमाटर का फसल-कैलेंडर	130
तालिका V.1	व्यवसायों को प्रभावित करने वाले विनियमन क्षेत्रों और प्रावधानों की सूची	155
तालिका V.2	व्यवसायों को प्रभावित करने वाले कानूनों में सुधार के लिए संभावित दृष्टिकोण की सूची	158
तालिका VI.1	शहरों के मूल्यांकन के लिए मानक समान फ्रेमवर्क के तहत उपलब्धि	185
तालिका XI.1	विद्यालय के अवसंरचना में सुधार (मूलभूत सुविधाओं वाले विद्यालयों का प्रतिशत)	311
तालिका XI.2	आयुष्मान आरोग्य मंदिर का फैक्ट शीट	334
तालिका XI.3	पीएम-एबीएचआईएम का फैक्टशीट	335
तालिका XI.4	एबीडीएम का फैक्टशीट	337
तालिका XI.5	एनसीडी द्वारा विकसित स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना	346
तालिका XI.6	ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित विकास योजनाओं की प्रगति	351
तालिका XI.7	डीएवाई एनआरएलएलएम के प्रमुख कार्यक्रम घटकों के अंतर्गत प्रगति	359
तालिका XI.8	मनरेगा पर मुख्य संकेतक	360
तालिका XII.1	रोजगार के स्वरुप, लिंग और स्थान के आधार पर औसत आय (2023-24 के लिए)	380
तालिका XII.2	आय के रूझान	380
तालिका XII.3	कुछ देशों में समयोपरि कार्य विनियम	393
तालिका XII.4	शिक्षा कौशल और व्यवसायों के बीच बेमेल का मैट्रिक्स	401
तालिका XII.5	भारत की कौशल विकास पहल को आगे बढ़ाना	402

चार्ट की सूची

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट I.1	वर्ष 2024 में समुत्थानशील वैश्विक विकास के रुझान	3
चार्ट I.2	कंट्री ग्रुप्स में स्थिर विकास की संभावना	3
चार्ट I.3	जर्मन अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमियाँ	4
चार्ट I.4	सिटी इकोनॉमिक सरप्राइज इंडेक्स अमेरिका के अप्रत्याशित समुत्थानशीलता का संकेत देता है	4
चार्ट I.5	नवंबर 2024 में वैश्विक विनिर्माण स्थिरता	5
चार्ट I.6	उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पीएमआई विनिर्माण	5
चार्ट I.7	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पीएमआई विनिर्माण	5
चार्ट I.8	उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति	6
चार्ट I.9	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति	6
चार्ट I.10	वैश्विक शिपिंग कीमतें अपने अधिकतम से कम हुई हैं	7
चार्ट I.11	विभिन्न वस्तु समूहों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव	8
चार्ट I.12	वस्तु की कीमतों में गिरावट का अनुमान	8
चार्ट I.13	फेडरल फंड्स दर के दीर्घकालिक स्तर पर अनिश्चितता में वृद्धि	8
चार्ट I.14	उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरें	9
चार्ट I.15	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत दरें	9
चार्ट I.16	उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल	9
चार्ट I.17	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल	9
चार्ट I.18	भू-राजनीतिक जोखिम (जीपीआर) सूचकांक वर्ष 2024 में अधिक है	10
चार्ट I.19	2024 में बढ़ा हुआ विश्व व्यापार अनिश्चितता सूचकांक (डब्ल्यूटीयूआई)	10
चार्ट I.20	वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, भारत की वृद्धि दशकीय औसत (स्थिर मूल्यों पर) के निकट बनी हुई है	11
चार्ट I.21	समग्र जीवीए में पुन:प्राप्ति जारी है	13
चार्ट I.22	कृषि जीवीए उच्च स्तरों पर कायम है	13
चार्ट I.23	औद्योगिक जीवीए रूझान स्तर से ऊपर परिचालित हो रहा है	13
चार्ट I.24	सेवा जीवीए रूझान स्तर के करीब है	13
चार्ट I.25	निर्माण जीवीए रुझान स्तर से काफी ऊपर चल रहा है, और विनिर्माण जीवीए में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है	13
चार्ट I.26	सेवा क्षेत्र में असमान सुधार	14
चार्ट I.27	वैश्विक मंदी ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण को प्रभावित किया	16
चार्ट I.28	व्यावसायिक अपेक्षाओं में सुधार	16
चार्ट I.29	वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि 6.0 प्रतिशत रही	17
चार्ट I.30	सभी वर्षों में पहली छमाही में निजी उपभोग का उच्चतम हिस्सा	17

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट I.31	सकल घरेलू उत्पाद में निवेश और उपभोग का स्थिर हिस्सा (वर्तमान मूल्यों पर)	18
चार्ट I.32	शीर्ष 8 शहरों में उच्च आधार पर आवास बिक्री और लॉन्च में नरमी	19
चार्ट I.33	सामान्य सरकारी अधिव्यय पर नियंत्रण ने वृहद-स्थिरता में योगदान दिया है	20
चार्ट I.34	सामान्य सरकारी जीएफसीएफ वृद्धि समग्र निवेश वृद्धि से अधिक रहा है	20
चार्ट I.35	राजकोषीय अनुशासन पर विशेष ध्यान	21
चार्ट I.36	वित्त वर्ष 25 में केंद्रीय वित्त की सुदृढ़ और सुनिश्चित स्थिति	21
चार्ट I.37	केंद्रीय करों में हिस्सेदारी पर अधिक निर्भरता	22
चार्ट I.38	अधिकांश स्वयं करों द्वारा प्रदर्शित वृद्धि	22
चार्ट I.39	ओटीआर पर निर्भरता का वितरण राज्यों में विविध परिदृश्य	23
चार्ट I.40	स्वयं के राजस्व संग्रह और राजस्व खाते की स्थिति के बीच सहसंबंध	23
चार्ट I.41	विविध दृष्टिकोण से राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	23
चार्ट I.42	वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में राज्यों के पूंजीगत व्यय में वृद्धि की उम्मीद	24
चार्ट I.43	आवंटन दक्षता संबंधी विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है	24
चार्ट I.44	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की बदलती स्थिति	24
चार्ट I.45	पूंजीगत व्यय और राजकोषीय स्थिति के मध्य सहसंबंध	25
चार्ट I.46	खाद्य कीमतों का दबाव खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ा रहा है	26
चार्ट I.47	टीओपी वस्तुओं को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति काफी कम है	26
चार्ट I.48	सेवा व्यापार अधिशेष और बाह्य क्षेत्र के लिए निजी अंतरण ऋण संतुलन	27
चार्ट I.49	सकल एफडीआई प्रवाह मजबूत रहने के बावजूद प्रत्यावर्तन में वृद्धि	28
चार्ट I.50	विभिन्न क्षेत्रों को बैंक ऋण की वृद्धि में मंदी	29
चार्ट I.51	स्थिर बैंकिंग प्रणाली संकेतक	30
चार्ट I.52	रोजगार संकेतकों में सुधार	31
चार्ट II.1	दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार उच्च मनी मल्टीप्लायर, जो बाजार में उच्च तरलता के संकेत को दर्शाता है	37
चार्ट II.2	पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा गुणक में हुई वृद्धि	38
चार्ट II.3(क)	एससीबी के जीएनपीए में गिरावट	39
चार्ट II.3(ख)	सीआरएआर अपेक्षित मानदंडों से काफी अधिक है	39
चार्ट II.4(क)	एससीबी की परिसंपत्तियों पर रिटर्न (वार्षिकीकृत)	40
चार्ट II.4(ख)	एससीबी की इक्विटी पर रिटर्न (वार्षिकीकृत)	40
चार्ट II.5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण संवितरण	41
चार्ट II.6	भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नए क्रेडिट अप-चक्र की शुरुआत देखी जा रही है	42
चार्ट II.7	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की क्रॉस-कंट्री तुलना	43
चार्ट II.8	व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) निवेश में रुझान	57

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट II.9	एसएंडपी500 बनाम एसएंडपी500 (समान भार) सूचकांक	58
चार्ट II.10	अमेरिकी कॉर्पोरेट लाभ बनाम गैर-तकनीकी कॉर्पोरेट लाभ	59
चार्ट II.11(क)	सक्रिय व्यक्तिगत निवेशकों की संख्या	60
चार्ट II.11(ख)	खुदरा निवेशकों द्वारा निवल अंतर्वाह	60
चार्ट II.12	एनएसई के नकदी बाजार खंड में व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा निवल अंतर्वाह का वार्षिक रुझान	60
चार्ट II.13	वित्तीय विकास और वृद्धि ख्र एक घंटी के आकार का संबंध	76
चार्ट III.1	वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि	81
चार्ट III.2	फ्रेंडशोरिंग और व्यापार संकेन्द्रण प्रवृत्तियाँ वैश्विक व्यापार को आकार प्रदान करती हैं	83
चार्ट III.3	2024 में वैश्विक व्यापार में उछाल	84
चार्ट III.4	कवरेज और आवृत्ति के आधार पर एनटीएम का वर्गीकरण	87
चार्ट III.5	माल व्यापार में रुझान	94
चार्ट III.6	पिछले दशक में भारत का कपड़ा निर्यात	95
चार्ट III.7	प्रमुख कपड़ा फाइबरों (रेशों) की विश्व खपत	97
चार्ट III.8	फाइबर के लिए वैश्विक बाजार में कपास की बाजार हिस्सेदारी	97
चार्ट III.9	महत्वपूर्ण पीसी के लिए खोजे गए नए बाजारों की संख्या	99
चार्ट III.10	वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में निवल सेवा आय में वृद्धि	100
चार्ट III.11	चालू खाता घाटे की प्रवृत्ति	105
चार्ट III.12	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष	105
चार्ट III.13	निवल पूंजी अंतर्वाह में तिमाही रुझान	106
चार्ट III.14	सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में रुझान	107
चार्ट III.15	एफडीआई (वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही) में क्षेत्रीय रुझान - कुल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में हिस्सेदारीज	108
चार्ट III.16	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह में मिश्रित प्रवृत्ति	111
चार्ट III.17	एफपीआई द्वारा ऋण खंड में निवल प्रवाह	112
चार्ट III.18	10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों(जी-सेक) के औसत मासिक प्रतिफल का रुझान	112
चार्ट III.19	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में उतार-चढ़ाव	114
चार्ट III.20	अप्रैल से दिसंबर 2024 तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले प्रमुख देशों की द्विपक्षीय विनिमय दरों में परिवर्तन'	115
चार्ट III.21	आरईईआर (वास्तविक प्रभावी विनिमय दर) और एनईईआर (अंकित प्रभावी विनिमय दर) में रुझान	115
चार्ट III.22	भारत की स्थिर विदेशी ऋण की स्थिति	116
चार्ट IV.1(क)	विभिन्न देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी	121
चार्ट IV.1(ख)	मौद्रिक लक्ष्यीकरण ने वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति को कम किया और उत्पादन को स्थिर किया	121
चार्ट IV.2	कोर मुद्रास्फीति भी कम हुई है	121

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट IV.3(क)	वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट	122
चार्ट IV.3(ख)	कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग प्रवृत्ति आलेख	122
चार्ट IV.4	हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति नियंत्रण में	123
चार्ट IV.5	सब्जियों और दालों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति	123
चार्ट IV.6(क)	टमाटर की खुदरा कीमतों में वृद्धि 2024 में उच्च अस्थिरता का संकेत देती है	124
चार्ट IV.6(ख)	2024 में प्याज की खुदरा कीमतें ऊंची बनी रहीं	124
चार्ट IV.7	हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति कुछ खाद्य वस्तुओं से प्रेरित	124
चार्ट IV.8	पिछले 3 वर्षों मे हीटवेव में वृद्धि हुई	125
चार्ट IV.9	मौसम की स्थिति के कारण क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र	125
चार्ट IV.10	अप्रैल-2020 से दिसम्बर-2024 में परवर्ती महीनों में मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाली चरम मौसम की घटनाओं की उच्चतर आवृत्ति	126
चार्ट IV.11	प्रमुख टमाटर और प्याज उत्पादक राज्यों में 2024 में अधिक हीटवेव का अनुभव हुआ	127
चार्ट IV.12	विभिन्न क्षेत्रों में प्याज उत्पादन की प्रवृत्ति	128
चार्ट IV.13	विभिन्न क्षेत्रों में टमाटर उत्पादन की प्रवृत्ति	128
चार्ट IV.14	घरेलू खपत उत्पादन से कम है	129
चार्ट IV.15	तुअर उत्पादन और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति	130
चार्ट IV.16	अगले दो वर्षों में पण्य वस्तुओं (कमोडिटी) की कीमतों में नरमी आएगी	132
चार्ट V.1	वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2030 तक आईएमएफ डब्ल्यूईओ का भारत के लिए अनुमान	136
चार्ट V.2	नए आयात-प्रतिबंधात्मक उपायों का व्यापार कवरेज	140
चार्ट V.3	व्यापार और निवेश संबंधी प्रतिबंधों का विस्तार	141
चार्ट V.4	वैश्विक संरचनात्मक शक्तियों में परिवर्तन	141
चार्ट V.5	वैश्विक औद्योगिक उत्पादन की बदलती संरचना	143
चार्ट V.6	जलवायु परिवर्तन के साथ विकास का लेखा-जोखा	144
चार्ट V.7	भारत की संस्थापित क्षमता मिश्रण [2022 बनाम 2030]	145
चार्ट V.8	विद्युत उत्पादन के हिस्से में परिवर्तन	145
चार्ट V.9	देश और क्षेत्र के अनुसार सौर पीवी विनिर्माण, 2010	146
चार्ट V.10	देश और क्षेत्र के अनुसार सौर पीवी क्षमता, 2021	146
चार्ट VI.1	अवसंरचना में पूंजीगत व्यय में प्रगति	167
चार्ट VI.2	केंद्र सरकार का समग्र पूंजीगत व्यय	167
चार्ट VI.3	रेलवे नेटवर्क की शुरूआत	168
चार्ट VI.4	वैगनों और इंजनों के उत्पादन में वृद्धि	168
चार्ट VI.5	वंदे भारत ट्रेनों की संचयी संख्या	168
चार्ट VI.6	वंदे भारत कोचों के उत्पादन संचयी संख्या	168

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट VI.7	राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण	171
चार्ट VI.8	विमान पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता	173
चार्ट VI.9	आरसीएस के तहत प्रचालित विमान पत्तन और मार्ग	173
चार्ट VI.10	पत्तन क्षमता में वृद्धि	173
चार्ट VI.11	प्रमुख पत्तनों में औसत कंटेनर टर्नअराउंड समय में कमी	173
चार्ट VI.12	सागरमाला कार्यक्रम में प्रगति (नवंबर 2024 तक)	174
चार्ट VI.13	विद्युत क्षेत्र में क्षमता वृद्धि	176
चार्ट VI.14	अक्षय ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता	176
चार्ट VI.15	दूरसंचार अवसंरचना में प्रगति	178
चार्ट VI.16	ओडीएफ प्लस स्थिति वाले गांवों में प्रगति	181
चार्ट VI.17	ओडीएफ प्लस दर्जा प्राप्त करने वाले गांवों की संख्या में वृद्धि	182
चार्ट VI.18	एसबीएम-यू के अंतर्गत प्रगति'	184
चार्ट VI.19	एसबीएम-यू के अंतर्गत संचयी प्रगति	184
चार्ट VI.20	स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाएं	186
चार्ट VI.21	स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियां	187
चार्ट VI.22	पर्यटन अवसंरचना विकास	189
चार्ट VII.1 (क और ख)	विनिर्माण क्षेत्र में चयनित देशों का प्रदर्शन	194
चार्ट VII.2 (क और ख)	उद्योग में विभिन्न घटकों और क्षमता उपयोग में वृद्धि	195
चार्ट VII.3 **(क और ख)**	संभावनाओं के बारे में सकारात्मकता	196
चार्ट VII.4 **(क और ख)**	सीमेंट उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता	197
चार्ट VII.5 **(क और ख)**	इस्पात उत्पादन और खपत में निरंतर वृद्धि	198
चार्ट VII.6 **(क और ख)**	रसायन और पेट्रोकेमिकल्स में हाल के उत्पादन रुझान	199
चार्ट VII.7	पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है	199
चार्ट VII.8	ऑटोमोबाइल' में समग्र, मिश्रित विकास रुझान	200
चार्ट VII.9	मजबूत उत्पादन रूझान	201
चार्ट VII.10 **(क और ख)**	वित्त वर्ष 25 में कपड़ा निर्यात में वृद्धि	202
चार्ट VII.11 **(क और ख)**	भारत में बौद्धिक संपदा तेजी से बढ़ रही है	204
चार्ट VII.12	भारत में अनुसंधान एवं विकास व्यय में तेजी की आवश्यकता	207
चार्ट VII.13 **(क और ख)**	निजी क्षेत्र का अनुसंधान एवं विकास व्यय कम और केंद्रित है	209
चार्ट VII.14	उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर बढ़ता पंजीकरण	210
चार्ट VII.15	कुल जीवीए में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी	213
चार्ट VII.16	औद्योगिक गतिविधि में एकाग्रता	213
चार्ट VII.17	स्थिर मूल्यों पर वित्त वर्ष 23 के कुल जीएसवीए में औद्योगिक जीएसवीए और उसके घटकों का हिस्सा	214

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट VII.18	औद्योगीकरण के स्तरों में विशाल अंतर-राज्यीय अंतर	215
चार्ट VII.19	औद्योगिक गतिविधि के सामान्य पैटर्न से भिन्न निर्माण गतिविधि का पैटर्न	216
चार्ट VII.20	प्रति व्यक्ति कारखानों (क्षैतिज अक्ष) और प्रति व्यक्ति अनिगमित विनिर्माण प्रतिष्ठानों (ऊर्ध्वाधर अक्ष) के बीच कमजोर सहसंबंध	217
चार्ट VII.21	व्यापार करने में आसानी ने औद्योगिक गतिविधि में सकारात्मक योगदान दिया है	218
चार्ट VIII.1	वर्ष 2023 में जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार सेवाओं का मूल्यवर्धन और दशकीय परिवर्तन	222
चार्ट VIII.2	वैश्विक सेवाओं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी	222
चार्ट VIII.3	सेवा जीवीए में वृद्धि	223
चार्ट VIII.4	जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी	223
चार्ट VIII.5	मजबूत बुनियादी सिद्धांत के समर्थन से वित्त वर्ष 2025 में पीएमआई सेवाएं मजबूत रहेंगी	224
चार्ट VIII.6	सेवाओं के जीवीए के प्रतिशत के रूप में सेवाओं का निर्यात (लोक प्रशासन का निवल)	225
चार्ट VIII. 7	सेवा क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह	225
चार्ट VIII.8	जीवीए, निर्यात और रोजगार के संदर्भ में सेवा क्षेत्र की क्षेत्रीय हिस्सेदारी	226
चार्ट VIII.9	कार्यनीतिक सिफारिशों का सारांश	227
चार्ट VIII.10	रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक में प्रगति	228
चार्ट VIII.11	रेलवे माल यातायात में प्रगति	228
चार्ट VIII.12	एयरवेज यात्री यातायात में प्रगति	230
चार्ट VIII.13	एयरवेज कार्गो ट्रैफिक में प्रगति - अंतरराष्ट्रीय	231
चार्ट VIII.14	पत्तन यातायात में प्रगति : प्रमुख पत्तनों पर संभाला गया माल	231
चार्ट VIII.15	विभिन्न राज्यों में परिचालन जलमार्गों की नौगम्य लंबाई (कि.मी.)	232
चार्ट VIII.16	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन और पर्यटन के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय चार्ट	233
चार्ट VIII.17	घरेलू पर्यटकों की संख्या महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच रही है	233
चार्ट VIII.18	बकाया ऋण: आवासन और वाणिज्यिक रियल एस्टेट	234
चार्ट VIII.19	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का प्रदर्शन: राजस्व और रोजगार सृजन	235
चार्ट VIII.20	प्रति माह प्रति डेटा उपयोगकर्ता औसत वायरलेस डेटा उपयोग	237
चार्ट VIII.21	वित्त वर्ष 23 के लिए स्थिर मूल्यों पर सेवाओं में राज्यवार हिस्सेदारी	240
चार्ट VIII.22	कुल जीएसवीए में लोक प्रशासन का हिस्सा	241
चार्ट VIII.23	कुल जीएसवीए में सेवाओं का हिस्सा और प्रति व्यक्ति जीएसवीए सेवाएं (लोक प्रशासन के निवल)	241
चार्ट VIII.24	व्यापार और मरम्मत, होटल और रेस्तरां सेवाएं: राज्यों में तीव्रता और प्रति व्यक्ति जीएसवीए	242
चार्ट VIII.25	वित्तीय सेवाएं: राज्यों में तीव्रता और प्रति व्यक्ति जीएसवीए	243
चार्ट VIII.26	रियल ऐस्टेट, आवास स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं: राज्यों में तीव्रता और प्रति व्यक्ति जीएसवीए	243
चार्ट VIII.27	प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीएसवीए और प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए	244
चार्ट IX.1	कृषि क्षेत्र का नियमित प्रदर्शन	248

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट IX.2	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से आउटपुट के मूल्य में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)	248
चार्ट IX.3	पुष्पकृषि के अंतर्गत कार्य योग्य भूमि का वितरण	249
चार्ट IX.4	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात	249
चार्ट IX.5	चयनित फसलों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय तुलना, 2022	250
चार्ट IX.6	प्रमुख खरीफ फसलों का उत्पादन	252
चार्ट IX.7	सकल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि	254
चार्ट IX.8	सिंचाई के स्रोत	255
चार्ट IX.9	वर्ष 2000 से वार्षिक आधार पर वर्षा में गिरावट का प्रतिशत	255
चार्ट IX.10	अधिक/कम वर्षा वाले उप प्रभागों की संख्या	256
चार्ट IX.11 और IX.12	सिंचाई के अंतर्गत सबसे कम (झारखंड) और सबसे अधिक (पंजाब) क्षेत्र वाले राज्य	257
चार्ट IX.13	लघु सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र	258
चार्ट IX.14	फसल ऋण की स्थिति	259
चार्ट IX.15	गैर-संस्थागत ऋण की घटती हिस्सेदारी	260
चार्ट IX.16	जीएलसी में वृद्धि	261
चार्ट IX. 17	छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि	261
चार्ट IX.18	कृषि संधारणीयता का समग्र सूचकांक-राज्यवार	266
चार्ट IX.19	दुग्ध, मांस, अंडे और मछली के उत्पादन में वृद्धि	267
चार्ट X.1	वर्ष 2021-22 में अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रवाह	275
चार्ट X.2	वर्ष 1992 और 2023 में जी7 में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा खपत में जीवाश्म ईंधन का योगदान	283
चार्ट X.3	वर्ष 1992 और 2023 में जी7 में संसाधनों के माध्यम से प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग	284
चार्ट X.4	जी7 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की कीमतों में उतार-चढ़ाव	285
चार्ट X.5	भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता	289
चार्ट X.6	भारत में गैर - जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा में वृद्धि	290
चार्ट X.7	पर्यावरण के लिए सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग	296
चार्ट X.8	दिल्ली में दैनिक औसत माह-वार वायु गुणवत्ता सूचकांक	299
चार्ट XI.1	सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्तियां	305
चार्ट XI.2	शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय	305
चार्ट XI.3	उपभोग में शहरी-ग्रामीण अंतर में गिरावट	306
चार्ट XI.4	दिव्यांग बच्चों के लिए पहल	323
चार्ट XI.5	स्वास्थ्य नीति के प्रमुख स्तंभ	330
चार्ट XI.6	प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) और सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा	331
चार्ट XI.7	स्वास्थ्य संबंधी व्यय की प्रवृत्ति	332
चार्ट XI.8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य संबंधी व्यय की प्रवृत्ति	332

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट XI.9(क)	मानसिक स्वास्थ्य और एमएचक्यू	341
चार्ट XI.9(ख)	जीवन-प्रभाव (एमएचक्यू) पैमाना	341
चार्ट XI.10	मानसिक स्वास्थ्य और जीवनशैली	343
चार्ट XI.11	मानसिक स्वास्थ्य और कार्य न कर पाने के दिन/माह	344
चार्ट XII.1	विभिन्न देशों में औसत आयु, जो भारत की अपेक्षाकृत युवा जनसंख्या को दर्शाती है	364
चार्ट XII.2(क)	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)8 और जीवन प्रत्याशा	365
चार्ट XII.2(ख)	निर्भरता अनुपात	365
चार्ट XII.3	कार्यशील आयु वर्ग के लोगों की अनुमानित संख्या और कुल जनसंख्या	365
चार्ट XII.4(क)	सामान्य स्थिति, आयु 15 वर्ष और उससे अधिक	367
चार्ट XII.4(ख)	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, आयु 15 वर्ष और उससे अधिक	
चार्ट XII.5	तिमाही आधार पर शहरी बेरोजगारी में गिरावट	367
चार्ट XII.6(क)	2023-24 के लिए राज्यों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात	368
चार्ट XII.6(ख)	2023-24 के लिए राज्यों में श्रम बल भागीदारी दर	368
चार्ट XII.7(क)	व्यापक श्रेणीवार रोजगार स्थिति का रुझान	370
चार्ट XII.7(ख)	व्यापक श्रेणीवार रोजगार स्थिति का रुझान: लैंगिक आधार पर	370
चार्ट XII.8(क)	2023-24 में व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा श्रमिकों का वितरण	371
चार्ट XII.8(ख)	व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा सामान्य स्थिति में महिला श्रमिकों का प्रतिशत वितरण	371
चार्ट XII.8(ग)	व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा सामान्य स्थिति में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत वितरण	371
चार्ट XII.9	महिला एलएफपीआर में सभी राज्यों में वृद्धि	372
चार्ट XII.10(क)	नकद और वास्तविक नियमित वेतन/वेतनभोगी रोजगार	380
चार्ट XII.10(ख)	सार्वजनिक कार्य के अलावा अन्य अनियत श्रम कार्य के लिए नकद और वास्तविक मजदूरी	381
चार्ट XII.10(ग)	स्व-रोजगार श्रमिकों के लिए नकद और वास्तविक मजदूरी	381
चार्ट XII.11(क)	पुरुषों की नकद ग्रामीण मजदूरी में सालाना वृद्धि	382
चार्ट XII.11(ख)	पुरुषों की वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में सालाना वृद्धि	382
चार्ट XII.12	4000 सूचीबद्ध संस्थाओं के प्रमुख मापदंडों में वृद्धि	383
चार्ट XII.13	समग्र कारखाना रोजगार और प्रति कारखाना रोजगार में वृद्धि	384
चार्ट XII.14	वित्त वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति परिलब्धियों में वृद्धि जबकि प्रति व्यक्ति निवल वर्धित मूल्य (एनवीए) स्थिर रहा	384
चार्ट XII.15	रोजगार में उच्च हिस्सेदारी दर्ज करने वाले उद्योग समूह	385
चार्ट XII.16	ईपीएफओ में ग्राहकों की निवल वृद्धि (लाख में)	386
चार्ट XII.17	औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट	389
चार्ट XII.18	कुछ देशों में औसत साप्ताहिक काम करने की समय की सीमा	392
चार्ट XII.19	अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों का हिस्सा	397

चार्ट संख्या	शीर्षक	पृष्ठ सं.
चार्ट XII.20	श्रमिकों का शैक्षिक स्तर	399
चार्ट XII.21	श्रमिकों का व्यावसायिक कौशल स्तर	399
चार्ट XII.22	2023-24 के लिए भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति	400
चार्ट XII.23	व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि	402
चार्ट XII.24	कौशल पिरामिड: एआई अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और न्यू स्किलिंग के लिए स्तरित रूपरेखा	406
चार्ट XIII.1	भारत के लिए सेवा क्षेत्रों में मांग लोच	434

बाक्स की सूची

बाक्स सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
बॉक्स II.1	आईबीसी और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण	50
बॉक्स II.2	वर्ष 2025 में भारतीय शेयर बाजार के लिए जोखिम	57
बॉक्स II.3	सुरक्षित सेवानिवृत्ति: भारत के पेंशन परिदृश्य में परिवर्तन	67
बॉक्स II.4	स्वतंत्र नियामक निकायों में नियामक प्रभाव आकलन को संस्थागत बनाना	69
बॉक्स II.5	क्या वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ सकती है?	75
बॉक्स III.1	टैरिफ और सफल औद्योगिक नीति रूपरेखा	85
बॉक्स III.2	सीबीएएम और ईयूडीआर तथा भारत के निर्यात पर उनका संभावित प्रभाव	88
बॉक्स III.3	अब समय आ गया है कि हम अपने ताने-बाने के बारे में सजग हो जाएं!	96
बॉक्स III.4	भारत के ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने वाले कारक	101
बॉक्स IV.1	खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक कदम	131
बॉक्स V.1	इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी विचार	146
बॉक्स V.2	ईओडीबी 2 के पक्ष में तर्क देना	159
बॉक्स VI.1	रेलवे में नव गतिविधियाँ	168
बॉक्स VI.2	रेलवे में यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए कदम	169
बॉक्स VI.3	रेलवे में सिग्नलिंग प्रणाली में सुधार के लिए प्रमुख पहल	170
बॉक्स VI.4	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास- परियोजना- आधारित दृष्टिकोण से कॉरिडोर आधारित दृष्टिकोण की ओर प्रगति	171
बॉक्स VI.5	सड़क कनेक्टिविटी में लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए प्रमुख पहल	172
बॉक्स VI.6	पत्तन क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां और पहल	174
बॉक्स VI.7	अंतर्देशीय जलमार्ग परिवर्तन: प्रमुख परियोजनाएं और पहल	175
बॉक्स VI.8	उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए फरवरी 2024 में शुरू किए गए उपाय	177
बॉक्स VI.9	दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करना	179
बॉक्स VI.10	डेटा सेंटर में क्षमता उन्नयन	179
बॉक्स VI.11	जल जीवन मिशन का प्रभाव	180
बॉक्स VI.12	अपशिष्ट प्रबंधन पहल की सफलता की कहानियाँ	182
बॉक्स VI.13	शहरी परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली पहल	187
बॉक्स VI.14	अंतरिक्ष आधारित अवसंरचना निगरानी प्लेटफार्म	190
बॉक्स VII.1	उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत के घरेलू विनिर्माण को सशक्त बनाना	201
बॉक्स VII.2	भारत का नवाचार परिदृश्य: प्रमुख मील के पत्थर	206
बॉक्स VII.3	अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन: एक वैश्विक तुलना	208
बॉक्स VII.4	ज्त्मकै रू समय पर भुगतान के माध्यम से एमएसएमई वित्तपोषण में बदलाव	210
बॉक्स VII.5	तमिलनाडु की फुटवियर विनिर्माण वृद्धि को बढ़ावा देने की रणनीतिक पहल	218
बॉक्स VIII.1	सेवाओं के लिए कार्यनीति - बहुआयामी विश्लेषण	226
बॉक्स VIII.2	नए खंड ख्र ड्रोन, लीजिंग और एमआरओ	230
बॉक्स VIII.3	भारत में सेवा क्षेत्र में एआई को अपनाना	236
बॉक्स VIII.4	सी-डॉट- भारत की दूरसंचार क्रांति का उत्प्रेरक	238
बॉक्स VIII.5	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क: प्लेटफॉर्म से परे सोचना	238
बॉक्स IX.1	भारत की पुष्प-कृषि: एक उभरता हुआ उद्योग	249

बाक्स सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
बॉक्स IX.2	ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव: बागवानी का उदय	251
बॉक्स IX.3	लघु सिंचाई: क्षमता का दोहन	258
बॉक्स IX.4	किसान ऋण पोर्टल: किसानों की समृद्धि के लिए कृषि ऋण को सुव्यवस्थित करना	261
बॉक्स IX.5	किसानों को सशक्त बनाना: एमएएचएएफपीसी (MAHAFPC) की सफलता की कहानी	264
बॉक्स IX.6	भूमि पट्टे के नवीन तरीके-केरल का मामला	264
बॉक्स IX.7	कृषि संधारणीयता का स्थानिक मानचित्रण	265
बॉक्स IX.8	देश में खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना को समर्थन देने के उपाय	270
बॉक्स X.1	वर्टिकल उद्यानों और पर्यावरण स्थिरता	278
बॉक्स X.2	मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगेबल इनकम्स (मिष्टी)	280
बॉक्स X.3	भारत के तटीय समुदायों की जलवायु संबंधी प्रतिरोधकता को बढ़ाना	281
बॉक्स X.4	उत्सर्जन के नए स्रोत: क्या उन पर विचार किया जा रहा है?	288
बॉक्स X.5	भारत में वनों का बढ़ता कार्बन सिंक	294
बॉक्स XI.1	पीडीएस से मिलने वाले लाभों के वितरण पर साक्ष्य	307
बॉक्स XI.2	ग्रामीण परिवारों के उपभोग विकल्प: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और स्वयं सहायता समूह	308
बॉक्स XI.3	सहकर्मी शिक्षण: एफएलएन प्राप्त करने का मार्ग	312
बॉक्स XI.4	एसईएल तकनीकों के माध्यम से समझ और हृदय को संवेदनशील बनाना	315
बॉक्स XI.5	जीवन कौशल प्रदान करना: टिम टिम तारे पहल	317
बॉक्स XI.6	कुशल और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।	320
बॉक्स XI.7	तमिलनाडु की इल्लम थेडी कल्वी (एजुकेशन एट डोरस्टेप): सार्वजनिक शिक्षा में नवाचार	321
बॉक्स XI.8	चिकित्सा शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ और उन पर कार्रवाई	326
बॉक्स XI.9	एरियल एंजल्स: स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में बदलाव	337
बॉक्स XI.10	सिलिकोसिस प्रबंधन में टेली-रेडियोलॉजी और एआई का उपयोग	339
बॉक्स XI.11	अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य पर प्रभाव	347
बॉक्स XI.12	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अनेक परिणाम	353
बॉक्स XI.13	संधारणीय विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण	355
बॉक्स XII.1	महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक	373
बॉक्स XII.2	महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल	376
बॉक्स XII.3	वेतन वृद्धि धीमी होने के बावजूद कॉर्पोरेट लाभप्रदता 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची	383
बॉक्स XII.4	श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने वाले श्रम कानून	387
बॉक्स XII.5	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, श्रम उत्पादकता और श्रम कानूनों की भूमिका	389
बॉक्स XII.6	नम्य श्रम नियम: रोजगार वृद्धि के लिए संतुलन कायम करना	391
बॉक्स XII.7	भारत का उभरता कौशल परिदृश्य	399
बॉक्स XII.8	रोजगार और कौशल विकास के लिए योजनाओं का पैकेज	405
बॉक्स XII.9	पीएम इंटर्नशिप योजना: प्रयोग करके सीखने के विचार को सर्वसुलभ बनाना	407
बॉक्स XII.10	कौशल विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	410
बॉक्स XIII.1	कृत्रिम बुद्धिमत्ता का रहस्योद्घाटन	427
बॉक्स XIII.2	कड़ियों को जोड़ना – रोजगार, स्वचालन और मांग-लोच	432